अनुदान मांग 2025-26 का विश्लेषण

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास मंत्रालय का लक्ष्य ग्रामीण भारत में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है और यह देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश विकास और कल्याणकारी गतिविधियों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।[1] मंत्रालय में दो विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग हैं। ग्रामीण विकास विभाग का उद्देश्य आजीविका के अवसरों को बढ़ाना, कमजोर वर्गों को सामाजिक सहायता प्रदान करना और ग्रामीण विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना है।[1] भूमि संसाधन विभाग का उद्देश्य वर्षा सिंचित खेती योग्य और बंजर भूमि का सतत विकास सुनिश्चित करना और देश में भूमि संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करना है।[2]

इस नोट में 2025-26 के लिए मंत्रालय के प्रस्तावित व्यय और पिछले वर्षों में बजट के रुझानों को स्पष्ट किया गया है। इसमें क्षेत्र के व्यापक रुझानों और कार्यक्रमों को लागू करने में मंत्रालय के सामने आने वाली चुनौतियों का भी विश्लेषण किया गया है।

वित्तीय स्थिति

2025-26 में आवंटन

2025-26 में ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,90,406 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।[3,4] ग्रामीण विकास विभाग को 1,87,755 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 8% अधिक है।[3] भूमि संसाधन विभाग को 2,651 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 35% अधिक है।[4]

तालिका 1: ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजटीय आवंटन (करोड़ रुपए में)

विभाग	23-24 वास्तविक	24-25 संअ	25-26 बअ	% परिवर्तन*
ग्रामीण विकास	1,61,932	1,73,912	1,87,755	8%
भूसंसाधन	1,711	1,966	2,651	35%
कुल	**1,63,643**	**1,75,878**	**1,90,406**	**8%**

नोट: बअ बजट अनुमान और संअ संशोधित अनुमान है।
*% परिवर्तन 2024-25 संअ की तुलना में 2025-26 बअ में परिवर्तन है।
स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगें 2025-26; पीआरएस।

बजट भाषण की मुख्य घोषणाएं (2025-26)[5]

- कौशल, प्रौद्योगिकी और निवेश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर पैदा करने के लिए एक रूरल प्रॉस्पैरिटी एंड रेज़िलियंस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम महिलाओं, युवाओं, किसानों और भूमिहीन परिवारों पर केंद्रित होगा।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसएचजी सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेंगे।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति

2021 तक भारत की 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 47% लोग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं।[6] 2024-25 में कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि का अनुमान है जो पिछले वित्तीय वर्ष की विकास दर (1.4%) से अधिक है।[7] हालांकि कृषि समग्र अर्थव्यवस्था की तुलना में लगातार धीमी गति से बढ़ी है। 2001-02 के बाद से कृषि उत्पादन 3% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है, जबकि शेष अर्थव्यवस्था 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी है।[8,9] इसके परिणामस्वरूप इस अवधि में कृषि उत्पादन दोगुना हो गया जबकि अर्थव्यवस्था का शेष हिस्सा 4.6 गुना बढ़ गया।

अत्रि प्रसाद राउत
atri@prsindia.org

4 फरवरी, 2025

रेखाचित्र 1: कृषि में वृद्धि समग्र आर्थिक वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर) से कम

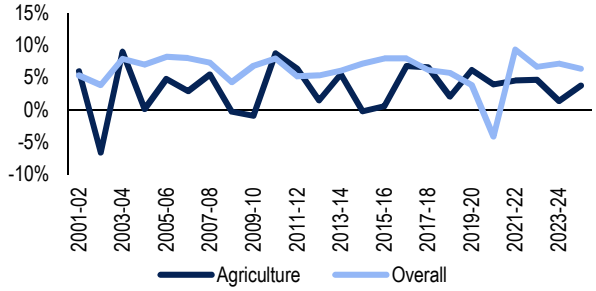

नोट: पहला अग्रिम अनुमान 2024-25 के लिए उपयोग किया गया है; कृषि में कृषि, वानिकी और फिशिंग शामिल है। स्रोत: सांख्यिकीय परिशिष्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, एमओएसपीआई; पीआरएस।

जनवरी और दिसंबर 2024 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में औसत खुदरा मुद्रास्फीति (5.4%) शहरी क्षेत्रों (4.4%) की तुलना में अधिक थी।[10] उच्च मुद्रास्फीति मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के कारण थी। आर्थिक सर्वेक्षण (2023-24) में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र मौसम की चरम घटनाओं, असमान वर्षा और निम्न जल स्तर से प्रभावित हुआ है।[11] इसके परिणामस्वरूप खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया था कि अच्छे दक्षिण-पश्चिम मानसून से कृषि उत्पादकता में सुधार और ग्रामीण मांग के पुनर्जीवित होने की उम्मीद है।[11] मुद्रास्फीति ने खपत को भी प्रभावित किया है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार, ग्रामीण औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) में मौजूदा कीमतों पर 9% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मुद्रास्फीति समायोजित वृद्धि 4% थी।[12]

रेखाचित्र 2: ग्रामीण औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय

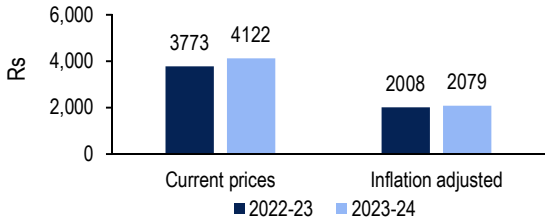

स्रोत: घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (2023-24), एमओएसपीआई; पीआरएस।

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (2023-24) में उपभोग व्यय में व्यापक असमानता भी दर्ज की गई। शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 71% अधिक था।[12] ग्रामीण आबादी के शीर्ष 5% (10,137 रुपए) हिस्से का औसत मासिक व्यय आबादी के निचले 5% (1,667 रुपए) हिस्से का लगभग छह गुना था।

अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (2024) के अनुसार, 2016 और 2021 के बीच बकाया ऋण वाले ग्रामीण परिवारों का अनुपात बढ़ गया है।[13,14]

तालिका 2: 52% ग्रामीण परिवारों पर कर्ज

परिवार	बकाया कर्ज वाले परिवारों का %	
	2016	2021
कृषि	52%	55%
गैर कृषि	43%	48%
कुल	**47%**	**52%**

स्रोत: अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण, नाबार्ड; पीआरएस।

कुछ बकाया ऋण वाले परिवारों में 2021 में कृषि परिवारों पर औसत ऋण 91,231 रुपए था, जबकि गैर-कृषि परिवारों पर औसत ऋण 89,074 रुपए था।[14] रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच में सुधार हुआ है, एक चौथाई परिवार (25%) अभी भी दोस्तों और रिश्तेदारों, जमींदारों और साहूकारों जैसे गैर-संस्थागत स्रोतों से ऋण लेते हैं।[14]

तालिका 3: 25% ग्रामीण परिवारों ने गैर-संस्थागत स्रोतों से ऋण लिया (2021-22)

स्रोत	कृषि परिवार	गैर कृषि परिवार	कुल परिवार
संस्थागत	76%	73%	74%
गैर संस्थागत	23%	26%	25%
दोनों	1%	1%	1%
कुल	**100%**	**100%**	**100%**

स्रोत: अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण, नाबार्ड; पीआरएस।

ग्रामीण क्षेत्रों में 2017-18 और 2023-24 के बीच 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) 25% से बढ़कर 48% हो गई है।[15] एफएलएफपीआर उन महिलाओं का प्रतिशत दर्शाता है जो या तो कामकाजी हैं या काम की तलाश में हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2023-24 के अनुसार, महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि ज्यादातर स्वरोजगार के माध्यम से हुई है।[15] महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर 2017-18 में 4% से घटकर 2023-24 में 2% हो गई है, जबकि पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% से घटकर 2023-24 में 3% हो गई है।

हालांकि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट (2024) में ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं की औसत आय में अंतर दर्ज किया गया है।[16]

तालिका 4: ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष और महिला श्रमिकों की औसत मासिक आय (रुपए में)

प्रकार	पुरुष	महिला	अंतर
स्वरोजगार प्राप्त	11,397	4,814	6,583
नियमित वैतनिक	16,319	10,567	5,752
आकस्मिक	8,831	5,451	3,380

नोट: आंकड़े 2022 के हैं; स्वरोजगार में अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक शामिल हैं और आकस्मिक में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिक शामिल हैं। स्रोत: भारत रोजगार रिपोर्ट 2024, आईएलओ; पीआरएस।

ग्रामीण विकास विभाग

वित्तीय स्थिति

ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने, कनेक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास को सहयोग देने और गरीबों एवं कमजोर लोगों के लिए आजीविका और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम लागू करता है।[17] विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) शामिल हैं।

2025-26 में विभाग को 1,87,755 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2014-15 और 2025-26 के बीच विभाग को बजटीय आवंटन औसतन 12% की वार्षिक दर से बढ़ा है। 2020-21 और 2022-23 के बीच महामारी के दौरान अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभाग को आवंटन में काफी बढ़ोतरी की गई थी। यह आवंटन मनरेगा और कल्याणकारी योजनाओं के लिए था, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण।[18]

रेखाचित्र 3: 2014-15 और 2025-26 के बीच व्यय (करोड़ रुपए में)

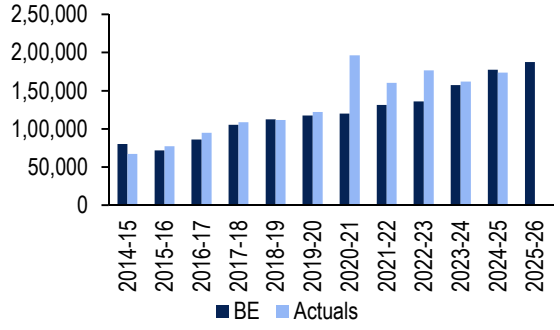

नोट: BE बजट अनुमान है; 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान वास्तविक के रूप में उपयोग किया गया है। स्रोत: विभिन्न वर्षों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगें; पीआरएस।

2018-19 को छोड़कर 2015-16 और 2023-24 के बीच विभाग का वास्तविक व्यय बजट अनुमान से अधिक था। 2024-25 में विभाग का संशोधित व्यय बजट अनुमान से 2% कम रहने की उम्मीद है। इसका मुख्य कारण प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत धनराशि का कम उपयोग होना है। 2020-21 और 2022-23 के बीच वास्तविक व्यय बजट अनुमान से अधिक था, मुख्य रूप से मनरेगा पर व्यय के कारण। मनरेगा एक मांग-आधारित योजना है, जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण काम की अधिक मांग देखी गई।

विभाग के तहत प्रमुख योजनाएं

2024-25 में विभाग को कुल आवंटन में मनरेगा (46%) और पीएमएवाई-जी (29%) का हिस्सा बजटीय आवंटन में 75% है। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और पीएमजीएसवाई (जिनमें से प्रत्येक विभाग के आवंटन का 10% हिस्सा है) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (5%) का स्थान आता है।

रेखाचित्र 4: व्यय की मुख्य मदें (कुल आवंटन के % के रूप में)

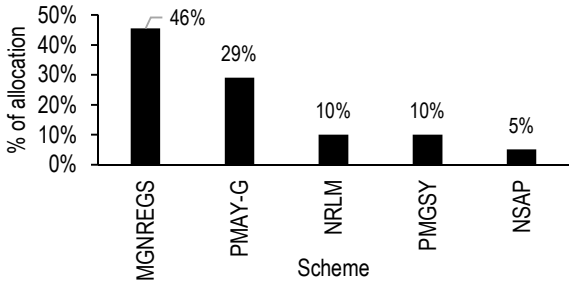

नोट: सकल व्यय पर % की गणना की गई है। स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांग, 2025-26; पीआरएस।

2025-26 में मनरेगा का आवंटन 2024-25 के संशोधित अनुमान के समान ही रहा है।

तालिका 5: प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन (करोड़ रुपए में)

योजना	2023-24 वास्तविक	2024-25 संअ	2025-26 बअ	% परिवर्तन
मनरेगा	89,154	86,000	86,000	0%
पीएमएवाई-जी	21,770	32,426	54,832	69%
एनआरएलएम	13,934	15,047	19,005	26%
पीएमजीएसवाई	15,380	14,500	19,000	31%
एनएसएपी	9,476	9,652	9,652	0%
सीएसएस	166	179	153	-14%

नोट: 2024-25 संअ से 2025-26 बअ तक % परिवर्तन; केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए सीएसएस में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के लिए आवंटन शामिल है। स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांग; पीआरएस।

प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, 2005 ग्रामीण परिवारों के वयस्कों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के गारंटीकृत रोजगार का प्रावधान करता है।[19] यह कानून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से पूरे देश में लागू किया गया है।[20] कार्यक्रम का उद्देश्य अकुशल शारीरिक कार्य के प्रावधान के माध्यम से ग्रामीण आजीविका में मदद करना है। यह योजना 100% शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर सभी जिलों में लागू है। योजना के माध्यम से काम की मांग करने वाले व्यक्ति को अगर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार है। योजना के तहत परियोजनाओं में सिंचाई के लिए नहरों की खुदाई, आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण, वृक्षारोपण अभियान, जलापूर्ति और स्वच्छता से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। (अनुलग्नक में तालिका 18 देखें।)

2025-26 के लिए इस योजना को 2024-25 के संशोधित अनुमान के समान 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चूंकि मनरेगा एक मांग आधारित योजना है इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम की मांग के अनुसार व्यय बढ़ता और घटता है। 2020-21 में इसमें 55% का उछाल आया क्योंकि कोविड-19 के दौरान लोग अपने-अपने गांव गए और उस दौरान काम की मांग बढ़ गई।[21] 15वें वित्त आयोग ने यह भी कहा था कि महामारी के दौरान कुल मांग में मंदी ने प्राथमिक क्षेत्र को प्रभावित किया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर रूप से असर पड़ा।[22]

रेखाचित्र 5: मनरेगा के लिए आवंटन (करोड़ रुपए में)

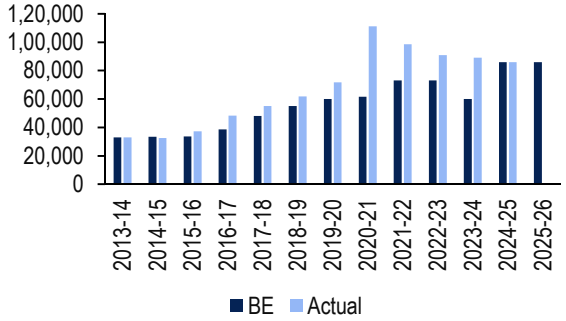

नोट: BE बजट अनुमान है। 2024-25 के लिए वास्तविक संशोधित अनुमान है। स्रोत: अनुदान की मांग, ग्रामीण विकास विभाग; पीआरएस।

योजना के तहत कार्य की मात्रा को श्रम दिवसों में मापा जाता है।[40] 2020-21 के दौरान उत्पन्न कार्य का कुल श्रम कार्य दिवस 389 करोड़ था।[23] अगले दो वर्षों में इसमें गिरावट देखी गई। 2024-25 में जनवरी 2025 तक उत्पन्न कुल श्रम दिवस 221 करोड़ था।[24] (अनुलग्नक में तालिका 19 देखें।)

रेखाचित्र 6: मनरेगा के जरिए उत्पन्न कार्य दिवस (करोड़ में)

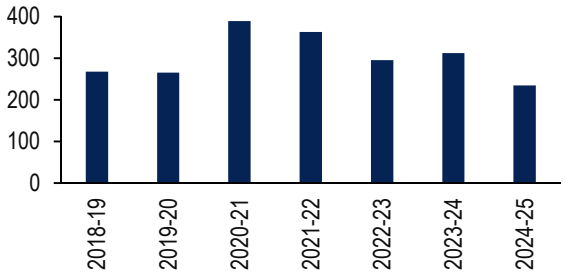

नोट: 2024-25 के आंकड़े जनवरी 2025 तक के हैं। स्रोत: मनरेगा डैशबोर्ड, 22 जनवरी 2025 को एक्सेस; पीआरएस।

ग्रामीण विकास से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने कोविड-19 महामारी जैसे संकट के दौरान ग्रामीण आबादी को सहायता प्रदान करने में योजना की भूमिका पर गौर किया था।[21] हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण (2023-24) में पाया गया कि मनरेगा के तहत काम की मांग को ग्रामीण संकट का वास्तविक संकेतक नहीं माना जा सकता है।[25] यह देखा गया कि योजना के तहत प्रदान किया गया कार्य अलग-अलग राज्यों की संस्थागत क्षमता से जुड़ा हुआ है। योजना के तहत धनराशि की उपलब्धता के लिए राज्यों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पहले से बजट बनाने की आवश्यकता है। इसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर योजना, बैठकें और अनुमोदन शामिल हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि सभी स्तरों पर प्रशिक्षित श्रमशक्ति वाले राज्य समय पर प्रक्रिया पूरी करते हैं, जिससे योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले कार्य पर असर होता है।[25]

रेखाचित्र 7: काम की मांग करने वाले 90% परिवारों को 2024-25 में मनरेगा के तहत काम मिला

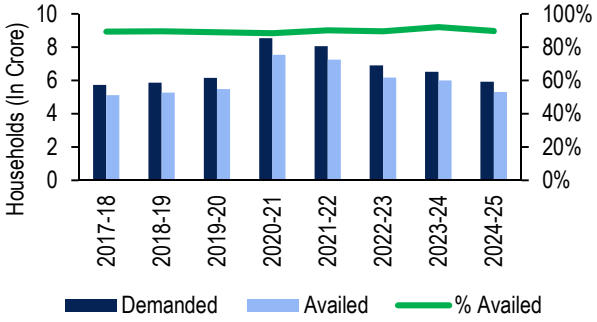

नोट: 2024-25 के आंकड़े, जनवरी 2025 तक के हैं। स्रोत: मनरेगा डैशबोर्ड, 22 जनवरी 2025 को एक्सेस; पीआरएस।

2023-24 में प्रति परिवार रोजगार के औसत दिनों और 100 दिनों का काम प्राप्त करने वाले परिवारों के प्रतिशत में वृद्धि देखी गई थी।[26] हालांकि 2024-25 में, दोनों संख्या में गिरावट देखी गई, केवल 4% परिवारों को 100 दिन का काम मिला, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 8% था।[24]

रेखाचित्र 8: 2023-24 में प्रति परिवार को दिए गए रोजगार के औसत दिन

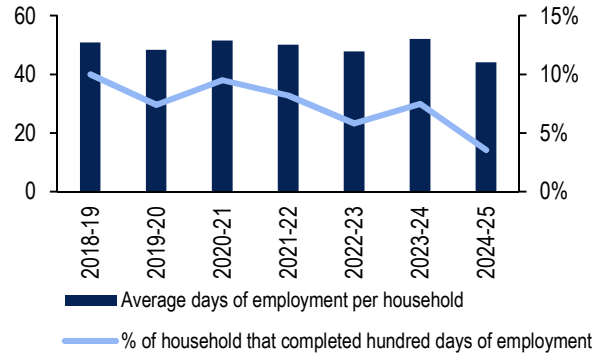

स्रोत: मनरेगा डैशबोर्ड, 22 जनवरी 2025 तक के आंकड़े; पीआरएस।

मनरेगा के तहत अपर्याप्त मजदूरी

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विकास मंत्रालय विभिन्न राज्यों के लिए मनरेगा श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी दरों को अधिसूचित करता है।[27] हालांकि श्रमिकों को दिया जाने वाला वास्तविक वेतन अक्सर अधिसूचित दर से कम होता है। 2024-25 में (जनवरी 2025 तक) 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी अधिसूचित मजदूरी दर से कम थी।[28]

तालिका 6: चुनिंदा राज्यों में अधिसूचित दैनिक मजदूरी दर और औसत भुगतान के बीच अंतर (रुपए में)

राज्य	अधिसूचित मजदूरी दर	चुकाई गई औसत मजदूरी
राजस्थान	266	211
तेलंगाना	300	245
तमिलनाडु	319	276
अंध्र प्रदेश	300	258
गुजरात	280	252
छत्तीसगढ़	243	227
कर्नाटक	349	333

नोट: औसत वेतन की गणना अप्रैल 2024 और जनवरी 2025 के लिए की गई है। स्रोत: मनरेगा डैशबोर्ड, ग्रामीण विकास मंत्रालय, 22 जनवरी 2025 को एक्सेस; पीआरएस।

मनरेगा मजदूरी भी राज्यों में अलग-अलग होती है क्योंकि वह कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) से जुड़ी होती है जो राज्यों में भिन्न होता है।[49] सीपीआई-एएल उन परिवारों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है जिनकी प्राथमिक आय कृषि श्रम से आती है।[29] ग्रामीण विकास से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2024) का कहना है कि जीवनयापन की बढ़ती लागत को देखते हुए मनरेगा के माध्यम से प्रदान की जाने वाली मजदूरी अपर्याप्त है।[30] वर्तमान में योजना के तहत मजदूरी दर की गणना के लिए वर्ष 2009-10 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग किया जाता है। कमिटी ने सुझाव दिया है कि मंत्रालय आधार को संशोधित करने पर विचार करे ताकि मजदूरी निर्धारण में मौजूदा मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को ध्यान में रखा जा सके।

लंबित मजदूरी का सीमित भुगतान

योजना के तहत, श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर और काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर किया जाता है।[34] देर से भुगतान की स्थिति में 16वें दिन के बाद से, मजदूर हर दिन मजदूरी का 0.05% हर्जाना पाने का हकदार है।[34] उदाहरण के लिए, अगर मजदूरी दर 300 रुपए प्रति दिन है, तो देरी के प्रति दिन का हर्जाना 15 पैसे होगा। 2024-25 के लिए श्रमिकों को मिलने वाले लंबित हर्जाने में से 26% का भुगतान जनवरी 2025 तक किया जा चुका था।[31]

तालिका 7: पांच वर्षों में स्वीकृत और भुगतान किए गए हर्जाने का % (रुपए में)

वित्तीय वर्ष	मंजूर राशि	चुकाई गई राशि	भुगतान का %
2020-21	1,38,43,589	1,14,88,940	83%
2021-22	1,78,46,651	1,44,22,191	81%
2022-23	93,61,395	60,75,919	65%
2023-24	54,88,967	13,68,324	25%
2024-25	31,32,118	8,13,364	26%

नोट: 2024-25 के आंकड़े, जनवरी 2025 तक के हैं। स्रोत: लंबित मजदूरी, मनरेगा डैशबोर्ड, एमओआरडी, 22 जनवरी 2025 को एक्सेस; पीआरएस।

राज्य सरकार मजदूरी में देरी के हर्जाने का भुगतान करने और देरी के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों या एजेंसियों से हर्जाना राशि वसूलने के लिए जिम्मेदार है।[32] कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा सत्यापन के बाद हर्जाना राशि को मंजूरी दी जाती है।[34] 2024-25 में जिन दिनों के लिए हर्जाने का दावा किया गया था, उनमें से 95% को हर्जाना देय नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया था।[31] मंत्रालय ने कहा है कि मजदूरी भुगतान में देरी को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे: (i) राज्य सरकारों के साथ नियमित परामर्श, (ii) जमीनी स्तर पर पर आवश्यक जनशक्ति की तैनाती, और (iii) इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करना।[33]

उचित सोशल ऑडिट की कमी

एक्ट के अनुसार, ग्राम सभा ग्राम पंचायत के भीतर योजना के तहत कार्यों की निगरानी करके जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।[19] यह निगरानी सोशल ऑडिट के माध्यम से होती है। राज्यों को स्वतंत्र सोशल ऑडिट इकाइयां स्थापित करनी होती हैं, जो ऑडिट की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्राम सभाओं को रिसोर्स पर्सन्स देती है।[34] ऑडिट के दौरान लाभार्थियों से संबंधित सभी रिकॉर्ड और योजना के तहत किए गए कार्यों का सत्यापन किया जाता है। हालांकि जनवरी 2025 तक 2,68,919 ग्राम पंचायतों में से केवल 56% (1,51,375) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कम से कम एक बार सोशल ऑडिट किए थे।[35]

रेखाचित्र 9: ग्राम पंचायतें जिन्होंने वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार सोशल ऑडिट पूरे किए

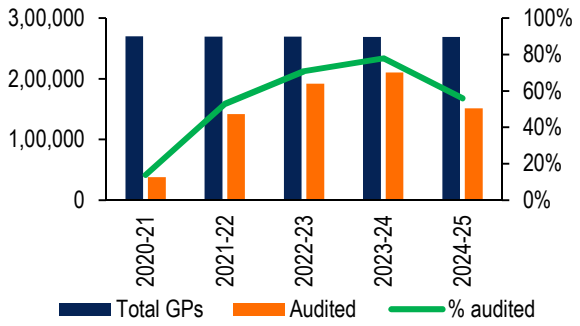

नोट: 2024-25 के आंकड़े, जनवरी 2025 तक के हैं।
स्रोत: सोशल ऑडिट कैलेंडर बनाम ऑडिट, मनरेगा डैशबोर्ड, एमओआरडी, 22 जनवरी, 2025 को एक्सेस; पीआरएस।

राज्य सरकार सोशल ऑडिट के निष्कर्षों के आधार पर सुधारात्मक उपाय करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें मजदूरी का भुगतान और योजना के तहत गलत तरीके से उपयोग किए गए धन की वसूली शामिल हो सकती है।[34] 2024-25 में सोशल ऑडिट के दौरान सामने आने वाली समस्याओं में से केवल 5% (7,70,410 में से 37,766) को जनवरी 2025 तक दूर और समाप्त किया गया था।[36] वित्तीय हेराफेरी के मामलों में से, 79% (9.21 लाख में से 7.31 लाख) का फैसला किया गया था।[37] राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (2018) द्वारा सोशल ऑडिट पर एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कई राज्यों को सोशल ऑडिट के लिए आवश्यक कर्मचारियों को नियुक्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राज्य योजना के तहत व्यय का 0.5% सोशल ऑडिट पर खर्च कर सकते हैं।[38] रिपोर्ट में पाया गया कि राज्यों, विशेष रूप से छोटे राज्यों ने उस राशि को अपर्याप्त पाया।[38] रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑडिट को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मंत्रालय को: (i) कैग के साथ ऑडिट की समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिए, (ii) फंडिंग में वृद्धि करनी चाहिए, और (iii) राज्यों को बेहतर अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करने को प्रोत्साहित करना चाहिए।[38]

बेरोजगारी भत्ते के भुगतान में देरी

एक्ट के तहत अगर किसी व्यक्ति को मांग के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वह व्यक्ति दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार है।[39] राज्य सरकारें निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार हैं: (i) बेरोजगारी भत्ते की दर निर्दिष्ट करना, (ii) भत्ते के भुगतान के लिए नियम बनाना, और (iii) भत्तों के लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान करना।[40] हालांकि 2019-20

और 2023-24 के बीच कुल देय बेरोजगारी भत्ते के मुकाबले 10% से कम का भुगतान किया गया।[41]

2024-25 में जनवरी 2025 तक देय बेरोजगारी भत्ते का 24% भुगतान किया जा चुका था।[42] जिन 14 राज्यों में 2024-25 में देय भत्ता था, उनमें से असम, ओड़िशा और उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए सभी भत्ते शामिल थे। (अनुलग्नक में तालिका 20 देखें।)

तालिका 8: भुगतान योग्य बेरोजगारी भत्ता और वास्तविक भुगतान (रुपए में)

वर्ष	भुगतान योग्य राशि	वास्तविक भुगतान	भुगतान का प्रतिशत
2019-20	30,30,253	31,106	1%
2020-21	58,06,966	2,40,530	4%
2021-22	1,66,30,106	2,63,137	2%
2022-23	89,92,628	10,49,600	12%
2023-24	20,91,940	1,85,798	9%
2024-25	9,08,317	2,21,147	24%

स्रोत: मनरेगा डैशबोर्ड, एमओआरडी, 25 जनवरी, 2025 को एक्सेस; पीआरएस।

बेरोजगारी भत्ता देने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।[43] मंत्रालय ने कहा कि वह राज्यों के साथ समीक्षा बैठकों के माध्यम से प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज (2022) से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी ने भत्तों के भुगतान में देरी और अनियमितताओं पर गौर किया था।[44] कमिटी ने विभाग से नोडल एजेंसी के रूप में भत्तों का उचित भुगतान सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। मंत्रालय ने कहा था कि वह सर्कुलर, एडवाइजरीज़ जारी करता है और केंद्रीय टीमों के निगरानी दौरों के माध्यम से राज्यों पर दबाव बनाता है।[44]

आर्थिक सर्वेक्षण (2023-24) में कहा गया था कि राज्यों की संस्थागत क्षमता इस बात को प्रभावित करती है कि योजना के तहत काम की मांग कैसे दर्ज की जाती है।[25] उसमें कहा गया था कि संभवतः अधिकारी रियल टाइम में काम की मांग दर्ज न करते हों। पोर्टल पर मांगे गए काम के आंकड़े, काम की वास्तविक मांग को न दर्शाते हों। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि इससे राज्यों द्वारा दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते पर असर पड़ता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

ग्रामीण आवास की मांग और आपूर्ति में अंतर को दूर करने के लिए 2016 में पीएमएवाई (ग्रामीण) को शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना है। सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 के आधार पर, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी 4.03 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था।[45]

पीएमएवाई (जी) का लक्ष्य दो चरणों में ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ पक्के मकान बनाने का था।[45] पहले चरण में 2016 से 2019 के बीच एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य था। दूसरे चरण में 2019 से 2022 के बीच 1.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य था।[45] 2022 तक दोनों चरणों के तहत कुल 2.10 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया था।[46] अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को 2028-29 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी।[47] ऐसा पिछले चरणों के शेष मकानों को पूरा करने और पांच वर्षों में दो करोड़ अतिरिक्त मकानों के निर्माण के लिए किया गया था।[47]

2025-26 के लिए इस योजना को 54,832 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 69% अधिक है। हालांकि 2024-25 के संशोधित अनुमान के अनुसार, योजना के लिए आवंटित धनराशि का 41% उपयोग नहीं किया गया था। मंत्रालय ने स्टैंडिंग कमिटी (2024) को जानकारी दी थी कि शेष राशि कई कारणों से खर्च नहीं हुई, जैसे: (i) राज्य केंद्रीय और अपना हिस्सा, दोनों वित्तीय वर्ष के अंत में एक साथ जारी करते हैं, और (ii) लंबे समय तक मानसून जैसे मौसमी कारकों से व्यय प्रभावित होता है।[74]

रेखाचित्र 10: पीएमएवाई (जी) के लिए आवंटित धनराशि (करोड़ रुपए में)

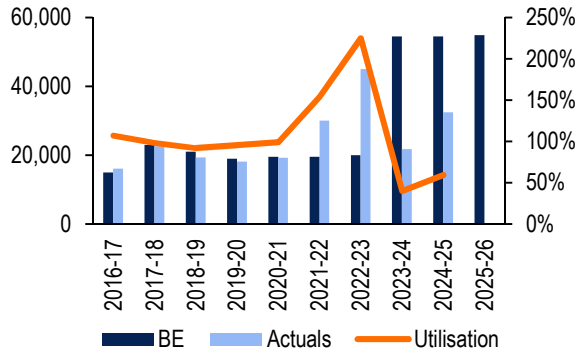

नोट: BE बजट अनुमान है। 2024-25 के लिए वास्तविक संशोधित अनुमान है। स्रोत: अनुदान की मांग, ग्रामीण विकास विभाग; पीआरएस।

मकानों के पूरा होने में देरी

3.79 करोड़ मकानों (2024-25 के लक्ष्य सहित) के लक्ष्य के मुकाबले, जनवरी 2025 तक कुल 2.69 करोड़ (71%) मकान पूरे हुए हैं।[48] (पिछले तीन वर्षों के लक्ष्य के मुकाबले पूरे किए गए मकानों के लिए अनुलग्नक में तालिका 21 और तालिका 22 देखें।)

तालिका 9: योजना के तहत वर्ष-दर-वर्ष पूर्ण मकानों की संख्या (लाख में)

	वर्ष	लक्ष्य	पूर्ण	पूर्णता की दर
चरण I	2016-17	42	0.02	0.05%
	2017-18	32	38	121%
	2018-19	25	45	179%
चरण II	2019-20	56	21	38%
	2020-21	42	34	82%
	2021-22	67	42	64%
	2022-23	23	56	242%
	2023-24	9	26	298%
	2024-25	84	4	5%

स्रोत: पीएमएवाई (जी) डैशबोर्ड, 22 जनवरी एक्सेस; पीआरएस।

मंत्रालय ने मकानों के पूरा होने में देरी के कई कारण बताए हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं: (i) लाभार्थियों की अनिच्छा, (ii) लाभार्थियों के पास जमीन की कमी, (iii) लाभार्थियों द्वारा धन का दुरुपयोग, (iv) कानूनी उत्तराधिकारी के बिना लाभार्थियों की मृत्यु, और (v) स्थायी प्रवास।[74] योजना के तहत अगर किसी लाभार्थी के पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है तो जमीन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। दिसंबर 2024 तक लगभग 2.12 लाख लाभार्थी योजना के तहत मकान बनाने के लिए भूमि या सहायता का इंतजार कर रहे थे।[74] स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने सुझाव दिया था कि मंत्रालय इन लाभार्थियों के लिए भूमि सुनिश्चित करने और बहुमंजिला आवास जैसे समाधान तलाशने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करे।[49] असम, बिहार, महाराष्ट्र और ओड़िशा में ऐसी योजनाएं हैं जो भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।[74]

रेखाचित्र 11: पीएमएवाई-जी के तहत लक्ष्य के मुकाबले पूर्ण मकानों का अनुपात (जनवरी 2025 तक)

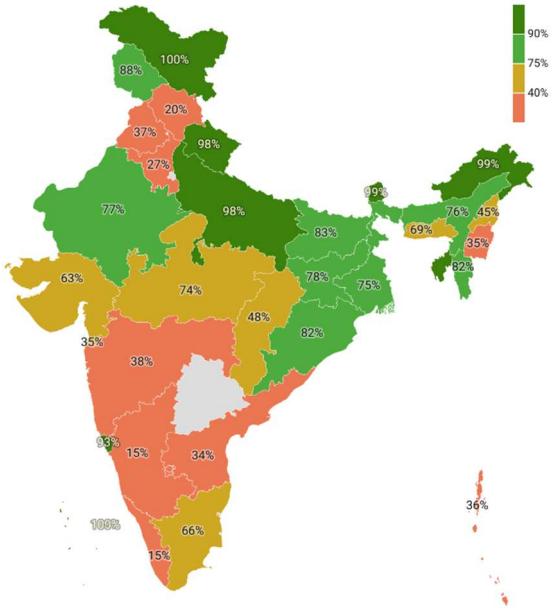

नोट: तेलंगाना और पूद्दूचेरी में पीएमएवाई-ग्रामीण योजना लागू नहीं है। इसमें 2024-25 में निर्धारित लक्ष्य शामिल हैं। स्रोत: पीएमएवाई-जी डैशबोर्ड, 31 जनवरी 2025 को एक्सेस; पीआरएस।

कार्यान्वयन और निगरानी

योजना के तहत, मैदानी इलाकों में रहने वाले लाभार्थियों को 1.2 लाख रुपए मिलते हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 1.3 लाख रुपए प्रति इकाई सहायता मिलती है।[49] यह राशि तीन से चार किस्तों में हस्तांतरित की जाती है जो मकान के निर्माण के विभिन्न चरणों से जुड़ी होती हैं। राज्यों में योजना के कैग (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) के ऑडिट में कार्यान्वयन और निगरानी से संबंधित कुछ मुद्दे सामने आए हैं। 2021 में मध्य प्रदेश में एक ऑडिट में पाया गया था कि पहली किस्त केवल 33% लाभार्थियों के लिए निर्धारित समय के भीतर जारी की गई थी।[50] कार्यान्वयन की संरचना के अनुसार, पहली किस्त मकान की मंजूरी के 15 दिनों के भीतर जारी की जानी चाहिए। 52% लाभार्थियों को छह महीने देर से किस्त जारी की गई थी। ओड़िशा (2021) में एक ऑडिट में पाया गया कि 43% सर्वेक्षण किए गए मकान (647 में से 277), जिन्हें पूरा दिखाया गया था, सत्यापन के दौरान अधूरे पाए गए।[51] 2022 में तमिलनाडु में एक ऑडिट में पाया गया कि: (i) रिकॉर्ड्स में मकान पूरा होने के चरण गलत तरीके से दिखाए गए थे, (ii) अलग-अलग लाभार्थियों के लिए एक ही मकान के फोटोग्राफ अपलोड किए जा रहे हैं, और (iii) निर्माण के विभिन्न चरणों के लिए अलग-अलग मकानों की तस्वीरें अपलोड की जा रही हैं।[52]

अगर कोई लाभार्थी योजना के माध्यम से प्रदान की गई राशि से अधिक खर्च करना चाहता है, तो वह वित्तीय संस्थानों से 3% की ब्याज सबसिडी के साथ 70,000 रुपए तक का गृह ऋण प्राप्त कर सकता है।[45] मध्य प्रदेश, ओड़िशा और पश्चिम बंगाल में योजना के 2018 के प्रभाव मूल्यांकन में पाया गया कि 80% लाभार्थियों ने मकान बनाने के लिए अतिरिक्त धन का निवेश किया।[53] हालांकि उनमें से 54% ने बिल्डिंग मैटीरियल सप्लायर से और 18% ने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसा उधार लिया। 5% से भी कम परिवारों ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों या राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से वित्तपोषण का लाभ उठाया था। स्टैंडिंग कमिटी (2024) ने सुझाव दिया था कि विभाग बिल्डिंग मैटीरियल की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए योजना के तहत प्रति इकाई सहायता बढ़ाए।[74] 2023 में कमिटी ने मंत्रालय को योजना के तहत लाभार्थियों का उचित सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए उपाय अपनाने का भी सुझाव दिया था।[49]

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खराब कनेक्टिविटी को खत्म करने के लिए 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) शुरू की थी।[54] यह योजना सभी पात्र ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। 2025-26 में इसे 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 31% अधिक है।

रेखाचित्र 12: पीएमजीएसवाई के तहत आवंटित और उपयोग धनराशि (करोड़ रुपए में)

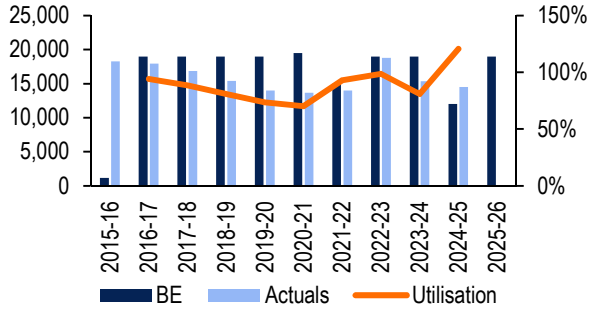

नोट: BE बजट अनुमान है। 2024-25 के लिए वास्तविक संशोधित अनुमान है। स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांग; पीआरएस।

पीएमजीएसवाई के पांच वर्टिकल हैं।[55,56] पहले वर्टिकल में मैदानी इलाकों में 500 से अधिक लोगों और उत्तर पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों में 250 से अधिक लोगों की आबादी वाली बस्तियों को सड़क संपर्क प्रदान करने का लक्ष्य है। दूसरे वर्टिकल का लक्ष्य 50,000 किमी सड़कों को अपग्रेड करना है जो रूट्स से होकर गुजरती हैं और प्रमुख लिंक के रूप में कार्य करती हैं। 2019 में तीसरा वर्टिकल शुरू किया गया था। इस लक्ष्य बाजारों और शहरी केंद्रों को जोड़ने वाले 1.2 लाख किमी सड़क मार्गों को समेकित करने का लक्ष्य है।[55] वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क कनेक्टिविटी परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) को 2016 में एक अलग वर्टिकल के रूप में शुरू किया गया था और इसे मार्च 2023 तक लागू किया जाना था।[57] मंत्रालय पीएम-जनमन के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों द्वारा बसे क्षेत्रों में सड़क निर्माण भी करता है।[58]

जनवरी 2025 तक योजना के तहत स्वीकृत 8,33,604 किमी सड़क में से 93% सड़कें पूरी हो चुकी हैं।[59] (रेखाचित्र 13) इसी प्रकार, 1.84 लाख पात्र बस्तियों में से 1.61 लाख (88%) को कवर किया गया है।[59] सितंबर 2024 में सरकार ने 62,500 किमी सड़कों के निर्माण के उद्देश्य से पीएमजीएसवाई-IV शुरू किया।[60] यह योजना 2024-25 और 2028-29 के बीच लागू की जाएगी और 25,000 बस्तियों को जोड़ेगी।

तालिका 10: पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के तहत स्वीकृत और पूर्ण सड़क की लंबाई (किमी में)

खंड	स्वीकृत	पूर्ण	पूर्णता की दर
पीएमजीएसवाई I	6,44,872	6,24,622	97%
पीएमजीएसवाई II	49,795	49,026	98%
पीएमजीएसवाई III	1,21,928	88,068	72%
आरसीपीएलडब्ल्यूईए	12,228	9,334	76%
जनमन	4,781	40	1%
कुल	**8,33,604**	**7,71,090**	**93%**

स्रोत: पीएमजीएसवाई डैशबोर्ड, एमओआरडी, 13 जनवरी 2025 को एक्सेस; पीआरएस।

तीसरे वर्टिकल, आरसीपीएलडब्ल्यूईए और पीएम-जनमन के लिए पूर्णता दर कम रही है। विभाग ने लक्ष्यों को प्राप्त करने में देरी के कई कारण बताए हैं, जैसे, (i) वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में कठिन इलाके और कानून व्यवस्था के मुद्दे, (ii) लॉजिस्टिक्स और इनपुट की आपूर्ति के प्रबंधन में चुनौतियां, और (iii) राज्यों द्वारा धनराशि जारी करने में देरी क्योंकि कार्यान्वयन उनके दायरे में है।[61] स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने विभाग से आग्रह किया था कि वह सभी क्षेत्रों में कार्य पूरा करने को प्राथमिकता दे और समय-समय पर अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से राज्यों के साथ समन्वय करे।[61] कमिटी (2024) ने कहा था कि कई मामलों में सड़कें केवल बस्तियों के बाहरी इलाकों तक ही पहुंचती हैं।[74] उसने मंत्रालय से यह सुनिश्चित

करने का आग्रह किया था कि सड़कें उन हिस्सों तक पहुंचे जहां अधिकांश आबादी रहती है।

सड़कों का रखरखाव

ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने वाले ठेकेदार, निर्माण पूरा होने के बाद पांच वर्षों तक रखरखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं।[62] इस अवधि के बाद सड़क रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। योजना के तहत सड़कों का गुणवत्ता निगरानी, काम पूरा होने के दौरान और उसके बाद, तीन स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के जरिए की जाती है।[63] इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ठेकेदार और परियोजना कार्यान्वयन इकाई के कर्मचारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर निरीक्षण, (ii) राज्य गुणवत्ता निरीक्षकों द्वारा स्वतंत्र आवधिक गुणवत्ता जांच, और (iii) राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षकों द्वारा चयनित कार्यों का निरीक्षण।[63] मार्च 2024 और जनवरी 2025 के बीच राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षकों द्वारा रखरखाव कार्य के निरीक्षण के दौरान 21% सड़कें (1,228 में से 257) असंतोषजनक पाई गईं।[64] इसी अवधि में राज्य गुणवत्ता निरीक्षकों द्वारा रखरखाव कार्य के निरीक्षण के दौरान 18% सड़कें (13,824 में से 2,423) असंतोषजनक पाई गईं।[65]

रेखाचित्र 13: जनवरी 2025 तक पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत सड़कों के पूर्ण होने का प्रतिशत

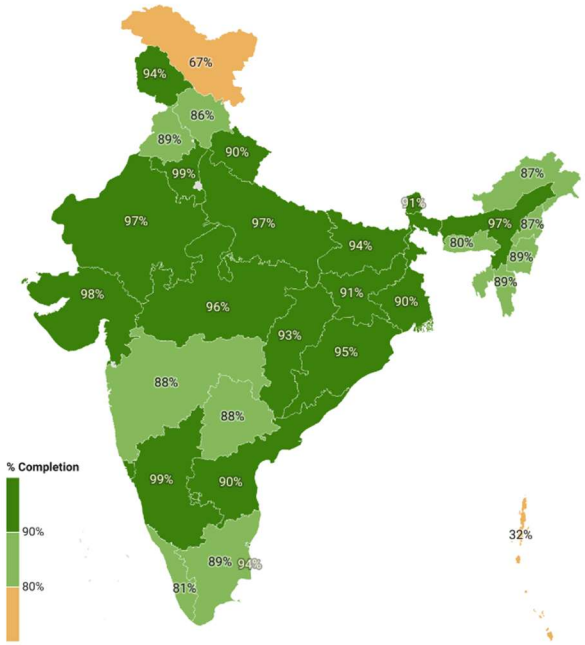

नोट: पीएमजीएसवाई-I, पीएमजीएसवाई-II, पीएमजीएसवाई-III और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के लिए कवर किए गए आंकड़े। स्रोत: पीएमजीएसवाई ऑनलाइन मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और एकाउंटिंग सिस्टम, एमओआरडी, 13 जनवरी, 2025 को एक्सेस; पीआरएस।

निर्माण के बाद के रखरखाव की निगरानी के लिए मंत्रालय द्वारा eMARG मॉड्यूल लागू किया जा रहा है।[61] इस मॉड्यूल ने निगरानी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है।[66] सड़क रखरखाव के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों को eMARG पोर्टल पर पंजीकरण कराना होता है।[67] रखरखाव कार्य के बिल ऑनलाइन जनरेट होते हैं। निरीक्षण एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से किया जाता है और सड़क के फोटोग्राफ जियो-टैगिंग के साथ अपलोड किए जाते हैं। रखरखाव की गुणवत्ता के आधार पर ठेकेदार के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। उस मूल्यांकन के आधार पर ठेकेदार को भुगतान किया जाता है।[67] बिलों को डिजिटल रूप से प्रोसेस और पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

यह प्रक्रिया रखरखाव कार्य की गुणवत्ता पर भुगतान को सशर्त बनाती है। पहले, ठेकेदार को भुगतान इनपुट की लागत के आधार पर किया जाता था।[67] हालांकि eMARG में मुख्य रूप से निर्माण के बाद के शुरुआती पांच वर्ष की दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) आती है।[66] जनवरी 2025 तक eMARG ने अप्रैल 2020 में स्थापना के बाद से डीएलपी के तहत आने वाली कुल 3,36,143 किमी सड़कों को कवर किया है।[68] डीएलपी के बाद की अवधि के तहत केवल 96,292 किमी की सड़कें अगस्त 2024 तक कवर की गई हैं।[67]

15वें वित्त आयोग ने सड़कों के रखरखाव में अंतर-राज्यीय असमानताओं पर गौर किया।[69] उसने मंत्रालय को अंतर-राज्यीय अंतराल को दूर का सुझाव दिया था और कहा था कि राज्य एक-दूसरे से सीखें। एक सुझाव यह था कि सड़क रखरखाव के लिए राज्यों को धन उपलब्ध कराया जाए। स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने भी इसी सुझाव को दोहराया था।[49] वर्तमान में सड़क रखरखाव कार्य के लिए बजट बनाने की जिम्मेदारी राज्यों की है। पीएमजीएसवाई-III के तहत, किसी राज्य में योजना शुरू करने से पहले राज्य को कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होते हैं।[70] इससे यह सुनिश्चित होता है कि राज्य निर्माण के बाद 10 वर्ष के नियमित रखरखाव के लिए धनराशि का आवंटन करेगा जिसमें जरूरी होने पर, सड़कों के नवीनीकरण की धनराशि भी शामिल होती है।

तालिका 11: सड़क रखरखाव में सुधार के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए गए मॉडल

राज्य	स्वीकृत मॉडल
छत्तीसगढ़, राजस्थान	कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ जोनल मेनटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड	सड़क रखरखाव के लिए एसएचजी को जिम्मेदार
मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान	सड़क रखरखाव के लिए मंडी उपकर का उपयोग किया जाता है

स्रोत: 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट, खंड III; पीआरएस।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का उद्देश्य गरीब परिवारों को वित्त और रोजगार के अवसरों तक पहुंच प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना है।[71] यह योजना स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से परिवारों को एकजुट करने और ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास करती है। सामुदायिक संसाधनों को मजबूत करने के लिए सरकार निम्नलिखित का एक बार का प्रावधान करती है: (i) प्रति एसएचजी 20,000 रुपए से 30,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड, और (ii) एसएचजी फेडरेशन के माध्यम से 2.50 लाख रुपए तक का सामुदायिक निवेश फंड।[72] एसएचजी-बैंक लिंकिंग कार्यक्रम के तहत यह ब्याज छूट के माध्यम से एसएचजी के लिए ऋण पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। 2025-26 में इस योजना के लिए 19,005 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 26% अधिक है।

रेखाचित्र 14: एनआरएलएम के तहत बजट उपयोग (करोड़ रुपए में)

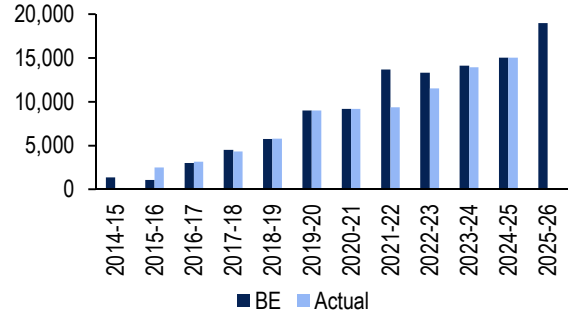

नोट: 2023-24 के लिए वास्तविक संशोधित अनुमान है। स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांग; पीआरएस।

जनवरी 2025 तक 10 करोड़ से अधिक परिवारों की भागीदारी के साथ, कार्यक्रम के तहत संचयी रूप से 91,75,483 एसएचजी को बढ़ावा दिया गया था।[73] दिसंबर 2024 तक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 21,94,755 एसएचजी को ऋण के रूप में 51,697 करोड़ रुपए वितरित किए गए थे।[74] (एसएचजी की राज्यवार संख्या के लिए अनुलग्नक की तालिका 23 देखें।)

रेखाचित्र 15: 2024-25 में एनआरएलएम के तहत एसएचजी को वितरित ऋण की औसत राशि (लाख रुपए में)

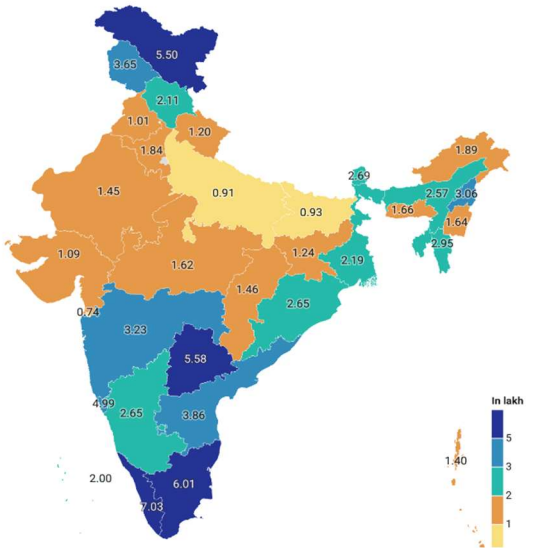

स्रोत: ग्रामीण विकास से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी की पहली रिपोर्ट, 18वीं लोकसभा, 12 दिसंबर, 2024; पीआरएस।

भारत में लघु वित्त पर नाबार्ड की स्टेटस रिपोर्ट (2023-24) में कहा गया है कि देश के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों ने अन्य क्षेत्रों की तुलना में एसएचजी को अधिक मात्रा में ऋण वितरित किए।[75] रिपोर्ट में कहा गया कि स्मॉल-टिकट ऋणों से जुड़ी उच्च परिचालन लागत और यह धारणा कि एसएचजी उच्च जोखिम वाले उधारकर्ता होते हैं (ऋण उपयोग से संबंधित चिंताओं के कारण), वित्तीय संस्थान ऋण देने से हिचकिचा सकते हैं। उसने यह भी कहा कि एसएचजी सदस्यों में अपर्याप्त वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक कौशल की कमी, उन्हें उच्च ऋण प्राप्त करने और आय सृजन गतिविधियों को आगे बढ़ाने से रोक सकती है।[75]

मंत्रालय ने कहा है कि वह बैंक अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए पहल करता है और एसएचजी सदस्यों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रदान की जाती है।[78] 2022 में उसने कहा था कि एसएचजी की ऋण चुकौती दर लगभग 98% है।[76] नाबार्ड रिपोर्ट में कहा गया कि एसएचजी के लिए बकाया ऋण में नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स की हिस्सेदारी 2021-22 में 4% से घटकर 2023-24 में 2% हो गई।[75] उसने कहा कि यह प्रवृत्ति परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार और ऋण पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में बैंकों के

प्रयासों को इंगित करती है।[75] इसके अलावा कार्यक्रम के तहत, बेहतर संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता के लिए एसएचजी को ग्राम संगठनों और क्लस्टर स्तर के संगठनों में संगठित किया जाता है।[77]

मंत्रालय के अनुसार, 2019 में कार्यक्रम पर एक मूल्यांकन अध्ययन से पता चला कि: (i) एसएचजी द्वारा लिए गए 44% ऋण का उपयोग कृषि गतिविधियों के लिए किया जाता है, (ii) 25% ऋण का उपयोग गाय, भैंस, बकरियों की खरीद और पशुधन से अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाता है, और (iii) 31% ऋण का उपयोग उपभोग, स्वास्थ्य और आवास के लिए किया जाता है।[78] अध्ययन में कहा गया है कि एसएचजी संस्थानों में भागीदारी का घरेलू आय, बचत और महिलाओं की श्रम बल भागीदारी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।[78]

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

एनआरएलएम के तहत, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के युवाओं को प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। हालांकि कार्यक्रम के तहत बनाए गए 2,369 प्रशिक्षण केंद्रों में से, जुलाई 2024 तक, 629 (26%) चालू थे।[74] 2016 और 2024 के बीच कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित 13,95,000 लोगों में से 9,53,000 (68%) को नौकरियां मिल गई थीं।[74] योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यक्रम को कम से कम 70% प्रशिक्षित उम्मीदवारों की गारंटीकृत नियुक्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।[79]

रेखाचित्र 16: योजना के तहत प्रशिक्षित और नियोजित व्यक्तियों की संख्या (हजारों में)

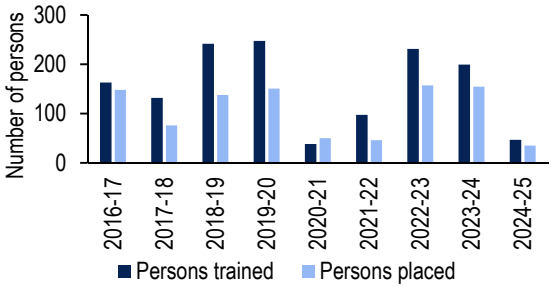

नोट: 2020 और 2021 में महामारी के कारण प्रशिक्षण केंद्र बंद कर दिए गए थे। स्रोत: ग्रामीण विकास से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी की पहली रिपोर्ट, 18वीं लोकसभा, 12 दिसंबर, 2024; पीआरएस।

भारत में कौशल विकास पहल से संबंधित एक रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (2020) ने कहा था कि स्कूली शिक्षा की खराब गुणवत्ता के कारण, कई प्रशिक्षु कम मूलभूत कौशल के साथ कौशल केंद्रों में प्रवेश करते हैं।[80] रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि प्रशिक्षण प्रदाताओं के पास अक्सर नए उपकरण, प्रशिक्षण विधियां और अपडेटेड पाठ्यक्रम नहीं होते हैं।[80] योजना के तहत, प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्तीय सहायता के अलावा, सरकार नौकरी बहाल रखने के लिए प्रवासन केंद्रों और एल्यूमनाई नेटवर्क के जरिए प्रशिक्षुओं की मदद करती है। मंत्रालय के अनुसार, योजना में संशोधन किया जा रहा है ताकि उम्मीदवारों का कौशल उन्नयन किया जा सके और न्यूनतम प्लेसमेंट अवधि को बढ़ाया जा सके।[81]

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 1995 में निराश्रित, वृद्ध, बीमार या विकलांग नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।[82] इसमें पांच उप-योजनाएं शामिल हैं, (i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), (iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस), (iv) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, और (v) अन्नपूर्णा योजना। यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तक फैली हुई है, और राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

इस योजना को पिछले वित्त वर्ष के संशोधित आवंटन के समान, 2025-26 में 9,652 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आवंटन में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 6,646 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए 659 करोड़ रुपए, विधवा पेंशन योजना के लिए 2,027 रुपए, विकलांगता पेंशन योजना के लिए 290 करोड़ रुपए और अन्नपूर्णा योजना के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 2020-21 में योजना के तहत अतिरिक्त आवंटन कोविड-19 महामारी के दौरान महिलाओं, वृद्ध लोगों और विधवाओं को विशेष हस्तांतरण के कारण था।[83]

तालिका 12: एनएसएपी के तहत धनराशि उपयोग (करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	% उपयोग
2015-16	9,074	8,616	95%
2016-17	9,500	8,854	93%
2017-18	9,500	8,694	92%
2018-19	9,975	8,418	84%
2019-20	9,200	8,692	94%
2020-21	9,197	42,443	461%
2021-22	9,200	8,152	89%
2022-23	9,652	9,651	100%
2023-24	9,636	9,476	98%
2024-25	9,652	9,652	100%
2025-26	9,652		

नोट: 2024-25 के लिए वास्तविक संशोधित अनुमान है। स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांगें; पीआरएस।

आईजीएनओएपीएस के तहत, गरीबी रेखा से नीचे के वरिष्ठ नागरिक 79 वर्ष की आयु तक 200 रुपए और उसके बाद 500 रुपए की मासिक पेंशन के हकदार हैं। जीवनयापन की बढ़ती लागत को देखते हुए संसद सदस्यों ने योजना के माध्यम से मासिक सहायता बढ़ाने का मुद्दा उठाया है।[84] सहायता राशि बढ़ाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने स्वयं के संसाधनों से केंद्र द्वारा प्रदान की गई राशि में कुछ अतिरिक्त राशि जोड़ी है।[85] यह 50 रुपए से लेकर 3,200 रुपए तक है।

ग्रामीण विकास से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2024) ने विभाग से धनराशि बढ़ाने का आग्रह किया था।[74] 15वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि राज्य देश भर में सामाजिक सुरक्षा पर खर्च की जाने वाली न्यूनतम मानकीकृत वार्षिक प्रति व्यक्ति राशि तय करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ समन्वय करें। कमिटी ने राज्यों से लाभार्थियों की सूची को सत्यापित और अपडेट करने के लिए वार्षिक ऑडिट करने का भी आग्रह किया था।[86]

2023 में योजना के कैग ऑडिट में कई राज्यों में धनराशि के वितरण में विलंब देखा गया।[87] राज्य के राजकोष से कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि हस्तांतरण में देरी के परिणामस्वरूप लाभार्थियों को मासिक पेंशन का वितरण नहीं हुआ। हालांकि एनएसएपी को मासिक भुगतान पेंशन माना जाता है, चार राज्य त्रैमासिक आधार पर पेंशन वितरित कर रहे थे, दो राज्य सालाना पेंशन वितरित कर रहे थे और 17 राज्य तदर्थ आधार पर धन वितरित कर रहे थे।

तालिका 13: राज्य के राजकोष से कार्यान्वयन विभाग को धनराशि हस्तांतरण में देरी

राज्य/यूटी	विलंब की अवधि
अरुणाचल प्रदेश	251 से 265 दिन
तमिलनाडु	117 से 287 दिन
महाराष्ट्र	39 से 189 दिन
सिक्किम	60 से 990 दिन
पंजाब	36 से 139 दिन

स्रोत: 2023 की रिपोर्ट संख्या 10, कैग; पीआरएस।

भूमि संसाधन विभाग

भूमि संसाधन विभाग का लक्ष्य वर्षा सिंचित और बंजर भूमि का सतत विकास सुनिश्चित करना और एक आधुनिक भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली लागू करना है।[88]

वित्तीय स्थिति

तालिका 14: भूमि संसाधन विभाग को बजटीय आवंटन (करोड़ रुपए में)

मद	23-24 वास्तविक	24-25 संअ	25-26 बअ	% परिवर्तन
पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी	1,565	1,800	2,505	39%
डीआईएलआरएमपी	124	141	120	-15%
सचिवालय	22	25	26	4%
कुल	**1,711**	**1,966**	**2,651**	**35%**

नोट: बअ बजट अनुमान है, संअ संशोधित अनुमान है; % परिवर्तन 2023-24 संअ की तुलना में 2024-25 बअ की % वृद्धि को दर्शाता है; पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- वॉटरशेड विकास घटक और डीआईएलआरएमपी डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम। स्रोत: भूमि संसाधन विभाग की अनुदान मांगें, 2025-26; पीआरएस।

2025-26 में विभाग को 2,651 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 35% अधिक है। 2013-14 के बाद से विभाग द्वारा वास्तविक खर्च लगातार बजटीय अनुमान से कम रहा है। 2024-25 में संशोधित स्थिति में विभाग की धनराशि का 74% उपयोग किया गया था।

रेखाचित्र 17: भूमि संसाधन विभाग द्वारा बजटीय आवंटन का उपयोग (करोड़ रुपए में)

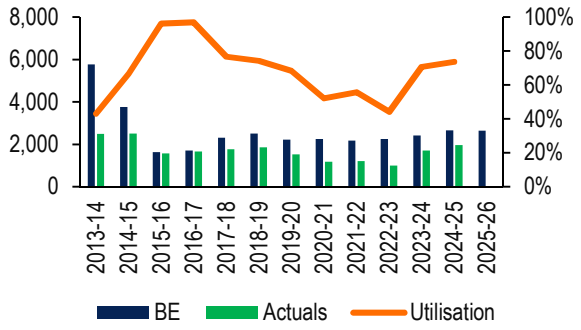

नोट: बअ बजट अनुमान हैं। 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान वास्तविक के रूप में उपयोग किया गया है। स्रोत: भूमि संसाधन विभाग के लिए अनुदान मांग; पीआरएस।

विभाग के तहत प्रमुख योजनाएं

विभाग दो प्रमुख योजनाएं लागू करता है: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- वॉटरशेड विकास घटक (पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी) और डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)। भूमि रिकॉर्ड के प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए 2016 में राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम को डीआईएलआरएमपी के रूप में नया रूप दिया गया।[89] योजना का उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड के बारे में व्यापक जानकारी तक पहुंच प्रदान करना है, जिससे (i) भूमि संसाधनों का इष्टतम उपयोग होगा, (ii) भूमि विवादों की संख्या में कमी होगी, और (iii) भूमि राजस्व का कुशल संग्रह होगा। पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी को वर्षा सिंचित और बंजर भूमि की उत्पादक क्षमता में सुधार के लिए लागू किया जा रहा है।[90] 2025-26 में विभाग के आवंटन में पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी विभाग का हिस्सा 94% है।

ग्रामीण विकास से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2022) ने कहा था कि विभाग के लिए आवंटन कम होने से विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के तहत खर्च कम हो सकता है।[91] दोनों योजनाओं के तहत, केंद्र सरकार द्वारा धनराशि हस्तांतरण तब होता है, जब राज्य प्रस्ताव सौंपते हैं। विभाग के अनुसार, राज्यों द्वारा अधूरे या लंबित प्रस्ताव के कारण केंद्र से धनराशि धीमी गति से जारी होता है।[92]

मुख्य मुद्दे और विश्लेषण

खर्च न होने वाली शेष राशि

ग्रामीण विकास से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2024) ने कहा था कि दोनों योजनाओं के तहत धनराशि काफी अधिक मात्रा में खर्च नहीं की गई।[93,94] 2022 में विभाग ने कहा था कि कोविड-19 महामारी, भारी बारिश और राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों को केंद्रीय धनराशि के लंबित हस्तांतरण के कारण यह राशि खर्च नहीं हो पाई।[95,96] कमिटी ने यह भी कहा कि राज्यों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति भी धीमी थी जिसके कारण शेष राशि जमा होती गई। इस समस्या को हल करने के लिए वित्त मंत्रालय ने यह शर्त तय की कि धनराशि तभी मंजूर की जाएगी, जब शेष राशि का उपयोग किया जाता है।[97]

तालिका 15: भूमि संसाधन विभाग की योजनाओं में खर्च न होने वाली शेष राशि (करोड़ रुपए में)

वर्ष	पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी	डीआईएलआरएमपी
2021-22	985	537
2022-23	1,241	648
2023-24	835	516
2024-25	784	540

नोट: खर्च न होने वाली शेष राशि में केंद्रीय हिस्सा, राज्य का हिस्सा और अर्जित ब्याज शामिल है। 31 जुलाई 2024 तक शेष धनराशि। स्रोत: दूसरी रिपोर्ट, ग्रामीण विकास से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी; 18वीं लोकसभा; पीआरएस।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- वॉटरशेड विकास घटक

2025-26 में पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी पर व्यय 2,505 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 39% अधिक है। 2015-16 से योजना का आवंटन 5% की वार्षिक दर (सीएजीआर) से बढ़ा है। साथ ही, योजना के तहत धनराशि उपयोग कम बना हुआ है, यहां तक कि कुछ वर्षों में 50% से भी कम। 2024-25 में संशोधित अनुमान बजट अनुमान का 72% है।

रेखाचित्र 18: पीएमकेएसवाई- डब्ल्यूडीसी के तहत बजटीय आवंटन और धनराशि उपयोग (करोड़ रुपए में)

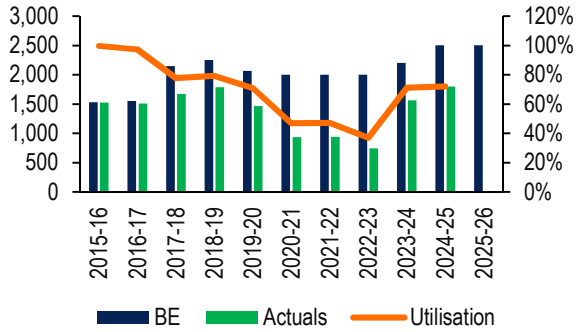

नोट: बअ बजट अनुमान हैं। 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान वास्तविक के रूप में उपयोग किया गया है। स्रोत: भूमि संसाधन विभाग के लिए अनुदान मांग; पीआरएस।

पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी के तहत अधूरी परियोजनाएं

पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी को दो चरणों में लागू किया जा रहा है। पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी 1.0 को 2009-10 से 2014-15 तक लागू किया गया था। पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी 2.0 को 2021-22 में शुरू किया गया था और इसके 2025-26 तक जारी रहने की उम्मीद है।

डब्ल्यूडीसी में बंजर भूमि के उपयोग में सुधार के लिए कई घटक हैं। इनमें वनीकरण, बागवानी और जल संचयन संरचनाओं का निर्माण शामिल है। इन सभी खंडों में काम की दर और लक्ष्य प्राप्ति अलग-अलग होती है।[98]

तालिका 16: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी के तहत विभिन्न घटकों के लक्ष्य और उपलब्धि

उपलब्धि (इकाई)	लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि
वनरोपण, कृषि के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	1,03,187	43,722	42%
बागवानी के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	1,46,805	52,299	36%
मृदा एवं नमी संरक्षण के अंतर्गत कवर किया गया क्षेत्र (हेक्टेयर)	16,33,589	2,06,907	13%
नव निर्मित जल संचयन संरचनाएं (संख्य)	1,95,348	58,318	30%
मरम्मत की गईं जल संचयन संरचनाएं (संख्या)	21,956	3,198	15%

स्रोत: रिपोर्ट टी2, पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी 2.0 एमआईएस, 22 जनवरी को एक्सेस; पीआरएस।

मंत्रालय ने कहा था कि चूंकि वॉटरशेड कार्य मौसमी प्रकृति के होते हैं, इससे धन का उपयोग प्रभावित होता है और शेष राशि खर्च नहीं हो पाती है।[94]

डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम

डीआईएलआरएमपी को 2025-26 में 120 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 15% कम है। 2017-18 से 2019-20 के बीच तीन वर्षों के अलावा, योजना के तहत धनराशि उपयोग 90% से अधिक रहा है।

भूमि रिकॉर्ड पर डेटा टेक्स्ट और स्पैशियल डेटा के रूप में उपलब्ध है।[100] टेक्स्ट डेटा में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के रिकॉर्ड शामिल हैं, जो भूमि के स्वामित्व, उसके उपयोग और सिंचाई की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। स्पैशियल डेटा में कैडेस्ट्रल मैप्स शामिल होते हैं जिनमें भूमि और सीमाओं के विभाजन के बारे में जानकारी होती है। कार्यक्रम के तहत, कैडेस्ट्रल मैप्स को आधुनिक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) एन्कोडिंग के साथ डिजिटलीकृत किया जा रहा है।

रेखाचित्र 19: डीएलआरएमपी के तहत बजटीय आवंटन और धनराशि उपयोग (करोड़ रुपए में)

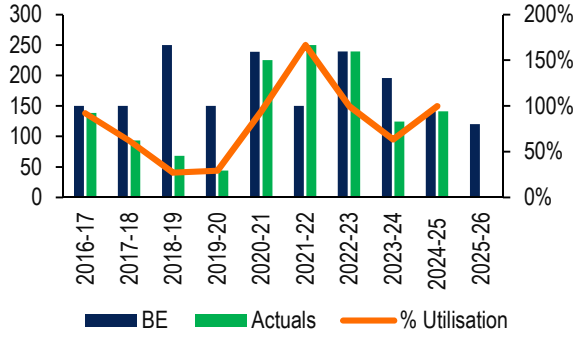

नोट: BE बजट अनुमान हैं। 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान वास्तविक के रूप में उपयोग किया गया है। स्रोत: भूमि संसाधन विभाग के लिए अनुदान मांग; पीआरएस।

घटकों की धीमी प्रगति

डीआईएलआरएमपी के आठ घटक हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण, (ii) कैडेस्ट्रल मैप्स का डिजिटलीकरण, (iii) कैडेस्ट्रल मैप्स को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स से जोड़ना, (iv) रिकॉर्ड रूम्स का आधुनिकीकरण, और (v) सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों के साथ भूमि रिकॉर्ड्स का एकीकरण।[99]

जमीनी वास्तविकता को दर्शाने के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड को अपडेट करना होता है।[100] मानचित्रों को तब बदलना होता है जब: (i) एक भूखंड को अधिक भूखंडों में विभाजित किया जाता है, (ii) एक भूखंड उपहार, बिक्री या विरासत के माध्यम से अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित किया जाता है। जब रिकॉर्ड में दिखाई गई सीमाएं ज़मीन पर वास्तविक स्थितियों से मेल नहीं खातीं तो पुनर्सर्वेक्षण आवश्यक हो जाता है। स्टैंडिंग कमिटी (2024) ने कहा था कि योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से भूमि रिकॉर्ड से संबंधित विवादों के समाधान में मदद मिल सकती है।[94] उसने मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि यह काम समय पर पूरा हो जाए। इससे पहले विभाग ने कहा था कि कुछ मामलों में धीमी प्रगति के कई कारण हैं, जैसे कुशल कर्मचारियों की कमी और राज्य सरकारों द्वारा देरी करना।[96]

तालिका 17: डीआईएलआरएमपी के तहत गतिविधियों में प्रगति

गतिविधि	उपलब्धि
रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का कंप्यूटरीकरण	99%
उप-पंजीयक कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण	100%
राजस्व अदालतों का कंप्यूटरीकरण	84%
कैडस्ट्राल मैप्स का डिजिटलीकरण	96%
सर्वेक्षण या पुनर्सर्वेक्षण पूर्ण	17%
रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (आरओआर) से लिंक्ड कैडस्ट्राल मैप्स	65%

स्रोत: डीआईएलआरएमपी एमआईएस, 25 जनवरी, 2025 को एक्सेस; पीआरएस।

अनुलग्नक

तालिका 18: 2024-25 में मनरेगा के तहत निर्मित परिसंपत्तियों के प्रकार (22 जनवरी, 2025 तक)

निर्माण की श्रेणी	इकाई	कुल लोक निर्माण (नया और पिछला स्टॉक)	व्यय	कुल का %
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित लोक निर्माण कार्य		**1,50,20,703**	**49,71,221**	**30%**
इनमें से				
जल संरक्षण	हेक्टेयर	40,69,702	11,54,594	8%
वॉटरशेड प्रबंधन	हेक्टेयर	10,91,937	8,20,217	2%
सिंचाई	हेक्टेयर	31,70,991	9,79,518	6%
पारंपरिक जलाशय	हेक्टेयर	11,81,269	7,34,228	2%
वनीकरण	हेक्टेयर	34,37,201	5,48,758	7%
भूमि विकास	हेक्टेयर	20,69,603	7,33,906	4%
कमजोर वर्गों के लिए सामुदायिक संपत्ति या व्यक्तिगत संपत्ति		**2,26,19,380**	**23,15,388**	**46%**
इनमें				
भूमि उत्पादकता में सुधार	हेक्टेयर	40,07,231	5,68,668	8%
आजीविका में सुधार	हेक्टेयर	29,57,103	2,27,140	6%
परती/बंजर भूमि का विकास	हेक्टेयर	11,19,022	2,83,502	2%
मकानो का निर्माण	संख्या	1,01,71,735	8,64,243	21%
पशुधन संवर्धन	संख्या	40,60,102	2,94,523	8%
मत्स्य संवर्धन	संख्या	3,04,187	77,311	1%
एनआरएलएम एसएचजी के लिए कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर		38,895	16,201	0.08%
इनमें				
कृषि उत्पादकता	हेक्टेयर	14,367	6,811	0.03%
स्व-सहायता समूहों की आजीविका गतिविधियों के लिए कॉमन वर्क-शेड	संख्या	24,528	9,390	0.05%
ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर		**1,15,75,668**	**27,96,931**	**24%**
इनमें				
ग्रामीण स्वच्छता	संख्या	44,94,843	1,56,720	9%
सड़क संपर्क/आंतरिक सड़कें/गलियां	किलोमीटर	44,17,776	16,04,859	9%
खेल के मैदान	संख्या	2,52,038	1,21,173	1%
आपदा तैयारी/बहाली	संख्या	15,17,638	5,61,272	3%
भवन निर्माण	संख्या	4,69,660	3,35,632	1%
खाद्यान्न भंडारण संरचनाएं	संख्या	96,313	12,991	0.20%
निर्माण के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री का उत्पादन	संख्या	64,663	1,791	0.13%
रखरखाव	संख्या	72,628	15	0.15%
अन्य लोक निर्माण कार्य	संख्या	1,90,109	2,478	0.39%
कुल		**4,92,54,646**	**1,00,99,741**	**100%**

स्रोत: वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए आर 6.3 मास्टर वर्क श्रेणी-वार विश्लेषण (नया+पिछला स्टॉक), नरेगा डैशबोर्ड, 22 जनवरी, 2025 को एक्सेस; पीआरएस।

तालिका 19: वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवारों द्वारा मांगे गए रोजगार और मनरेगा के तहत प्रदान किए गए रोजगार के बीच अंतर, साथ ही प्राप्त रोजगार के औसत दिन (22 जनवरी, 2025 तक)

राज्य	परिवारों द्वारा रोजगार की मांग	परिवारों को प्रदान किया गया रोजगार	अंतर	रोजगार के औसत दिन
आंध्र प्रदेश	49,25,607	49,21,908	3,699	46
अरुणाचल प्रदेश	2,98,186	2,97,847	339	53
असम	18,63,330	18,61,244	2,086	34
बिहार	51,90,155	51,82,232	7,923	45
छत्तीसगढ़	27,36,335	27,34,746	1,589	46
गोवा	2,694	2,587	107	22
गुजरात	9,40,768	9,38,241	2,527	45
हरियाणा	3,69,682	3,69,200	482	30
हिमाचल प्रदेश	7,12,011	7,11,719	292	50
जम्मू एवं कश्मीर	6,74,803	6,73,141	1,662	49
झारखंड	20,92,664	20,91,060	1,604	45
कर्नाटक	29,42,929	29,05,810	37,119	41
केरल	13,73,038	13,72,955	83	56
लद्दाख	32,957	32,939	18	65
मध्य प्रदेश	40,56,413	40,39,134	17,279	44
महाराष्ट्र	29,25,410	29,17,383	8,027	47
मणिपुर	5,13,787	5,13,482	305	35
मेघालय	4,43,233	4,43,057	176	49
मिजोरम	2,09,315	2,09,149	166	81
नगालैंड	2,35,867	2,30,604	5,263	34
ओड़िशा	23,00,494	22,97,250	3,244	46
पंजाब	8,99,286	8,97,823	1,463	34
राजस्थान	60,13,511	60,10,240	3,271	47
सिक्किम	60,378	60,348	30	49
तमिलनाडु	66,59,356	66,58,652	704	41
तेलंगाना	27,58,994	27,57,848	1,146	42
त्रिपुरा	6,00,153	6,00,130	23	56
उत्तर प्रदेश	68,06,724	68,06,177	547	48
उत्तराखंड	4,33,656	4,33,072	584	40
पश्चिम बंगाल	1	-	1	0
अंडमान एवं निकोबार	3,245	3,215	30	25
दादरा नगर हवेली और दमन दीव	4,280	4,279	1	52
लक्षद्वीप	-	-	-	0
पुद्दूचेरी	50,925	50,922	3	21
कुल	**5,91,30,187**	**5,90,28,394**	**1,01,793**	**45**

स्रोत: आर5.1.1 वर्ष 2024-2025 के दौरान सृजित रोजगार, मनरेगा डैशबोर्ड, ग्रामीण विकास मंत्रालय; 22 जनवरी 2025 को एक्सेस; पीआरएस।

तालिका 20: वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा के तहत राज्यों द्वारा भुगतान किया गया बेरोजगारी भत्ता (जनवरी 2025 तक)

राज्य	भुगतान की जाने वाली राशि	भुगतान की गई राशि	देय राशि	भुगतान का %
आंध्र प्रदेश	-	-	-	
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	
असम	53,535	8,342	45,193	16%
बिहार	27,746	-	27,746	0%
छत्तीसगढ़	-	-	-	
गोवा	-	-	-	
गुजरात	21,210	-	21,210	0%
हरियाणा	-	-	-	
हिमाचल प्रदेश	53,700	-	53,700	0%
जम्मू एवं कश्मीर	38,850	-	38,850	0%
झारखंड	476	-	476	0%
कर्नाटक	1,89,507	-	1,89,507	0%
केरल	1,817	-	1,817	0%
लद्दाख	-	-	-	
मध्य प्रदेश	851	-	851	0%
महाराष्ट्र	62,073	-	62,073	0%
मणिपुर	-	-	-	
मेघालय	-	-	-	
मिजोरम	-	-	-	
नगालैंड	-	-	-	
ओड़िशा	13,145	7,240	5,905	55%
पंजाब	-	-	-	
राजस्थान	2,993	-	2,993	0%
सिक्किम	-	-	-	
तमिलनाडु	-	-	-	
तेलंगाना	6,750	-	6,750	0%
त्रिपुरा	-	-	-	
उत्तर प्रदेश	4,35,665	2,05,565	2,30,100	47%
उत्तराखंड	-	-	-	
पश्चिम बंगाल	-	-	-	
अंडमान एवं निकोबार	-	-	-	
दादरा नगर हवेली और दमन दीव	-	-	-	
लक्षद्वीप	-	-	-	
पुद्दूचेरी	-	-	-	
कुल	**9,08,317**	**2,21,147**	**6,87,170**	**24%**

स्रोत: आर19.1 वित्तीय वर्ष में बेरोजगारी भत्ता: 2024-2025; नरेगा डैशबोर्ड, 22 जनवरी 2025 को एक्सेस; पीआरएस।

तालिका 21: पीएमएवाई-ग्रामीण के तहत संचयी लक्ष्य के मद्देनजर पूर्ण किए गए मकानों का अनुपात (जनवरी 2025 तक)

	एमओआरडी का लक्ष्य	स्वीकृत	पूर्ण	लक्ष्य बनाम पूर्ण
अरुणाचल प्रदेश	35,937	35,404	35,582	99%
असम	26,11,793	21,67,921	19,90,974	76%
बिहार	44,92,010	39,28,189	37,10,515	83%
छत्तीसगढ़	23,41,457	17,72,161	11,21,050	48%
गोवा	257	253	240	93%
गुजरात	9,02,354	7,81,951	5,64,855	63%
हरियाणा	1,06,460	31,441	28,795	27%
हिमाचल प्रदेश	1,21,502	92,922	24,080	20%
जम्मू एवं कश्मीर	3,36,498	3,33,155	2,95,137	88%
झारखंड	20,12,107	16,62,892	15,64,359	78%
केरल	2,32,916	62,135	34,097	15%
मध्य प्रदेश	49,89,236	40,49,223	36,87,490	74%
महाराष्ट्र	33,40,872	25,58,248	12,69,264	38%
मणिपुर	1,08,550	97,978	37,773	35%
मेघालय	1,88,034	1,82,890	1,29,505	69%
मिजोरम	29,967	29,542	24,593	82%
नगालैंड	48,830	48,085	21,978	45%
ओड़िशा	28,49,889	27,80,187	23,40,492	82%
पंजाब	1,03,674	61,956	38,750	37%
राजस्थान	22,15,247	18,72,955	17,00,136	77%
सिक्किम	1,399	1,373	1,386	99%
तमिलनाडु	9,57,825	7,39,889	6,33,145	66%
त्रिपुरा	3,76,913	3,72,974	3,67,787	98%
उत्तर प्रदेश	36,85,704	36,35,296	36,10,909	98%
उत्तराखंड	69,194	68,381	68,091	98%
पश्चिम बंगाल	45,69,423	44,23,752	34,19,112	75%
अंडमान एवं निकोबार	3,424	3,028	1,227	36%
दादरा और नगर हवेली	11,206	10,995	3,937	35%
दमन और दीव	158	127	24	15%
लक्षद्वीप	45	53	45	100%
पुद्दूचेरी	-	-	-	
आंध्र प्रदेश	2,47,114	1,67,931	83,826	34%
कर्नाटक	9,44,140	1,83,410	1,45,077	15%
तेलंगाना	-	-	-	
लद्दाख	3,004	3,004	3,004	100%
कुल	**3,79,37,139**	**3,21,59,701**	**2,69,57,235**	**71%**

नोट: इसमें 2024-25 में निर्धारित लक्ष्य भी शामिल हैं; स्रोत: पीएमएवाई-जी डैशबोर्ड, 31 जनवरी 2025 तक; पीआरएस।

तालिका 22: पीएमएवाई-ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के लक्ष्य के मददेनजर पूर्ण किए गए मकानों से संबंधित उपलब्धियां (जनवरी 2025 तक)

	2022-23			2023-24			2024-25		
	लक्ष्य	पूर्ण	पूर्णता का %	लक्ष्य	पूर्ण	पूर्णता का %	लक्ष्य	पूर्ण	पूर्णता का %
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-		-	-	
असम	-	-	-	2,19,778	1,80,492	82%	5,59,951	12,200	2%
बिहार	-	-	-	-	-		7,90,648	44,664	6%
छत्तीसगढ़	78,998	64,996	82%	-	-		11,65,315	15,379	1%
गोवा	-	-		-	-		-	-	
गुजरात	1,68,146	1,42,508	85%	-	-		2,99,011	344	0.1%
हरियाणा	-	-		-	-		77,058	-	0.0%
हिमाचल प्रदेश	-	-		13,690	7,969	58%	92,364	777	1%
जम्मू एवं कश्मीर	-	-		1,38,106	1,06,463	77%	-	-	
झारखंड	-	-		-	-		4,19,947	98	0.0%
केरल	-	-		-	-		1,97,759	7	0.0%
मध्य प्रदेश	-	-		-	-		11,89,690	9,154	0.8%
महाराष्ट्र	-	-		-	-		19,66,767	4,877	0.2%
मणिपुर	-	-		56,460	49	0%	7,000	-	0.0%
मेघालय	-	-		1,09,388	50,508	46%	-	-	
मिजोरम	-	-		9,459	1,410	15%	-	-	
नगालैंड	-	-		25,898	8,075	31%	-	-	
ओड़िशा	97,037	60,856	63%	-	-		1,24,304	8,137	7%
पंजाब	-	-		-	-		63,985	280	0.4%
राजस्थान	-	-		-	-		4,98,468	3,127	1%
सिक्किम	-	-		-	-		-	-	
तमिलनाडु	-	-		190	-	0%	2,10,623	11	0.01%
त्रिपुरा	73	52	71%	1,15,835	1,08,854	94%	-	-	
उत्तर प्रदेश	8,58,498	8,49,358	99%	1,44,201	1,41,377	98%	70,834	15,641	22%
उत्तराखंड	17,882	17,718	99%	22,544	21,811	97%	-	-	
पश्चिम बंगाल	11,01,723	-	0%	-	-		-	-	
अंडमान एवं निकोबार	257	-	0%	1,835	-	0%	-	-	
दादरा और नगर हवेली	-	-		4,738	44	1%	-	-	
दमन और दीव	-	-		100	-	0%	-	-	
लक्षद्वीप	-	-		-	-		-	-	
पुद्दूचेरी	-	-		-	-		-	-	
आंध्र प्रदेश	-	-		-	-		684	44	6%

कर्नाटक	-	-		-	-		7,02,731	216	0.03%
तेलंगाना	-	-		-	-		-	-	
लद्दाख	-	-		1,125	1,046	93%	-	-	
कुल	**23,22,614**	**11,35,488**	**49%**	**8,63,347**	**6,28,098**	**73%**	**84,37,139**	**1,14,956**	**1.4%**

स्रोत: पीएमएवाई-जी डैशबोर्ड, ग्रामीण विकास मंत्रालय, 3 फरवरी, 2025 को एक्सेस; पीआरएस।

तालिका 23: 2024-25 में एनआरएलएम के तहत एसएचजी को वितरित ऋण की राज्य-वार राशि (दिसंबर 2024 तक)

राज्य	एसएचजी की संख्या	संवितरित ऋण (करोड़ रुपए में)	ऋण प्रति एसएचजी (लाख रुपए में)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	10	0	1.40
आंध्र प्रदेश	3,43,710	13,283	3.86
अरुणाचल प्रदेश	356	7	1.89
असम	73,854	1,901	2.57
बिहार	3,96,806	3,690	0.93
छत्तीसगढ़	49,781	728	1.46
गोवा	162	8	4.99
गुजरात	16,778	182	1.09
हरियाणा	5,564	102	1.84
हिमाचल प्रदेश	2,647	56	2.11
जम्मू एवं कश्मीर	4,508	165	3.65
झारखंड	1,27,907	1,588	1.24
कर्नाटक	20,157	534	2.65
केरल	10,793	759	7.03
लद्दाख	2	0.11	5.50
लक्षद्वीप	6	0.12	2.00
मध्य प्रदेश	75,178	1,214	1.62
महाराष्ट्र	60,174	1,944	3.23
मणिपुर	1,022	17	1.64
मेघालय	3,594	60	1.66
मिजोरम	314	9	2.95
नगालैंड	523	16	3.06
ओड़िशा	1,41,752	3,759	2.65
पुद्दूचेरी	157	11	6.75
पंजाब	4,211	43	1.01
राजस्थान	42,054	611	1.45
सिक्किम	1,115	30	2.69
तमिलनाडु	19,419	1,167	6.01
तेलंगाना	1,20,722	6,736	5.58
दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव	23	0	0.74
त्रिपुरा	7,084	176	2.49
उत्तराखंड	12,787	153	1.20
उत्तर प्रदेश	1,16,854	1,059	0.91
पश्चिम बंगाल	5,34,731	11,690	2.19
कुल	**21,94,755**	**51,697**	**2.36**

स्रोत: ग्रामीण विकास से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी की पहली रिपोर्ट, 18वीं लोकसभा, 12 दिसंबर, 2024; पीआरएस।

[1] About the Ministry, Ministry of Rural Development, as accessed on June 15, 2024, https://rural.nic.in/en/about-us/about-ministry.
[2] About the Department, Department of Land Resources, as accessed on June 15, 2024, https://dolr.gov.in/en/about-us/about-department.
[3] Demand No 87, Department of Rural Development, Ministry of Finance, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe87.pdf.
[4] Demand No 88, Department of Land Resources, Ministry of Finance, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe88.pdf.
[5] Speech of the Minister of Finance, Budget 2025-26, February 1, 2025, https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_Speech.pdf.

[6] Economic Survey 2022-23, Ministry of Finance, https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf.
[7] FIRST ADVANCE ESTIMATES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, 2024-25, Ministry of Statistics and Programme Implementation, January 7, 2025, https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/PR_NAD_07012025_0.pdf.
[8] Back-series of National Accounts (Base 2011-12), Ministry of Statistics and Programme Implementation, https://www.mospi.gov.in/publication/back-series-national-accounts-base-2011-12.
[9] Statistical Appendix, Economic Survey (2023-24), Ministry of Finance, https://www.indiabudget.gov.in/budget2024-25/economicsurvey/doc/Statistical-Appendix-in-English.pdf.
[10] Consumer Price Index archives, MoSPI, as accessed on January 20, 2025, https://cpi.mospi.gov.in/Default1.aspx.
[11] Economic Survey 2023-24, Ministry of Finance, https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/.
[12] Household Consumption Expenditure Survey: 2023-24, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Press Information Bureau, December 27, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2088390.
[13] NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey 2016-17, August 2018, NABARD, https://www.nabard.org/auth/writereaddata/tender/1608180417NABARD-Repo-16_Web_P.pdf.
[14] NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey 2021-22, October 2024, NABARD, https://www.nabard.org/auth/writereaddata/tender/pub_0910240156351156.pdf.
[15] Annual Report, Periodic Labour Force Survey 2023-24, December 23, 2024, MoSPI, https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/AnnualReport_PLFS2023-24L2.pdf.
[16] India Employment Report 2024, International Labour Organisation, https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-08/India%20Employment%20-%20web_8%20April.pdf.
[17] About the Ministry, Ministry of Rural Development, as accessed on July 15, 2024, https://rural.gov.in/en/about-us/about-ministry
[18] Demand No. 87, Department of Rural Development, Ministry of Rural Development, Union Budget 2022-23, https://www.indiabudget.gov.in/budget2022-23/doc/eb/sbe87.pdf.
[19] The National Rural Employment Guarantee Act, 2005, Ministry of Law, Ministry of Rural Development, https://rural.gov.in/sites/default/files/nrega/Library/Books/1_MGNREGA_Act.pdf.
[20] Annual Master Circular 2024-25, Ministry of Rural Development, Department of Rural Development, https://nregaplus.nic.in/netnrega/WriteReaddata/Circulars/AMC_2024-25-English.pdf.
[21] Rural Employment through Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) – An insight into wage rates and other matters relating thereto, Thirty Seventh Report of Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj (2023-24), February 2024, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Rural%20Development%20and%20Panchayati%20Raj/17_Rural_Development_and_Panchayati_Raj_37.pdf?source=loksabhadocs.
[22] Finance Commission in Covid Times Report for 2021-26, Volume III, October 2020, Finance Commission, https://fincomindia.nic.in/asset/doc/commission-reports/XVFC-Vol-III-Union.pdf.
[23] R5.1.1 Employment Generated during the year 2020-21, MGNREGA Dashboard, Ministry of Rural Development, https://nreganarep.nic.in/netnrega/citizen_html/demregister.aspx?lflag=eng&fin_year=2020-2021&source=national&labels=labels&Digest=GVEtvTyMaktJ6zoZj/EYWg.
[24] R5.1.1 Employment Generated during the year 2024-2025, MGNREGA Reports, Ministry of Rural Development, accessed on January 22, 2025, https://nreganarep.nic.in/netnrega/citizen_html/demregister.aspx?lflag=eng&fin_year=2024-2025&source=national&labels=labels&Digest=O57D2k1AxQj89t4Y5xNiBg.
[25] Economic Survey 2023-24, Ministry of Finance, https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf.
[26] Employment Generated during 2023-24, MGNREGA Dashboard, Ministry of Rural Development, as accessed on July 15, 2024, https://nreganarep.nic.in/netnrega/citizen_html/demregister.aspx?lflag=eng&fin_year=2023-2024&source=national&labels=labels&Digest=MZ7EPgZ8ZwgnIaImm+t7hA
[27] State-wise wage rate for unskilled manual workers, Ministry of Rural Development, March 27, 2024, https://nregaplus.nic.in/netnrega/writereaddata/Circulars/2476Wage_Rate_notification_FY_2024-25.pdf.
[28] Average Wage Paid in Rs, MGNREA Dashboard, Ministry of Rural Development, as accessed on July 17, 2024, https://mnregaweb4.nic.in/netnrega/avg_wage_paid.aspx?fin_year=2022-2023&source=national&Digest=tcKvOx2xp47V1TJeb2KhXQ
[29] National Consumer Price Index Numbers, Ministry of Statistics and Programme Implementation, https://mospi.gov.in/112-national-consumer-price-index-numbers
[30] Rural Employment through Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) – An insight into wage rates and other matters relating thereto, Thirty Seventh Report of Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj (2023-24), February 2024, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Rural%20Development%20and%20Panchayati%20Raj/17_Rural_Development_and_Panchayati_Raj_37.pdf?source=loksabhadocs.
[31] R 14.1 Delayed compensation FY: 2024-25, MGNREGA Dashboard, Ministry of Rural Development, as accessed on January 22, 2025, https://mnregaweb4.nic.in/netnrega/state_html/delay_comp.aspx?lflag=eng&fin_year=2024-2025&source=national&labels=labels&Digest=O57D2k1AxQj89t4Y5xNiBg.
[32] Guidelines on compensation for delayed wages payments, Ministry of Rural Development, June 2014, https://rural.gov.in/sites/default/files/nrega/Library/Books/Guidelines_Compensation_delayed_wages_pay.pdf.
[33] Ministry has taken various steps to ensure timely payment of wages to workers under the MGNREGA, Ministry of Rural Development, Press Information Bureau, December 21, 2022, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1885507#:~:text=The%20State%20Government%20shall%20pay,per%20information%20provided%20by%20PFMS.
[34] MGNREGS Annual Master Circular 2024-25, Ministry of Rural Development, https://nregaplus.nic.in/netnrega/writereaddata/Circulars/AMC_2024-25-English.pdf.
[35] R.9.1.3 Social Audit Calendar vs Audits Completed, NREGA Dashboard, Ministry of Rural Development, as accessed on January 22, 2025, https://nreganarep.nic.in/netnrega/MISreport4.aspx.
[36] R9.3.1 Social Audit Action Taken Report, NREGA Report, Ministry of Rural Development, as accessed on January 25, 2025, https://mnregaweb4.nic.in/netnrega/SocialAuditFindings/SAU_action_taken_report.aspx?lflag=eng&fin_year=2023-2024&source=national&labels=labels&rep_type=SoA&Digest=7VZtMou+tJJjHiG3mCh9Zw.
[37] R 9.2.6 Financial Misappropriation Recovery Report, NREGA Report, Ministry of Rural Development, as accessed on January 25, 2025, https://mnregaweb4.nic.in/netnrega/SocialAuditFindings/SAU_FMRecoveryReport.aspx?lflag=eng&fin_year=2024-2025&source=national&labels=labels&rep_type=SoA&Digest=3uRMVt6308BGCW2QZYttXQ
[38] Social Audits Units in India, National Institute of Rural Development and Panchayati Raj, Ministry of Rural Development, April 2018, https://nirdpr.org.in/nird_docs/socialaudit/csa030718.pdf.
[39] Section 5, The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/6930/1/the_mahatma_gandhi_national_rural_employment_guarantee_act%2C_2005.pdf.

[40] MGNREGA Frequently Asked Questions, Ministry of Rural Development, https://rural.gov.in/sites/default/files/MGNREGA_FAQ_ENGLISH.pdf.
[41] Unemployment Allowance in Financial Year 2023-24, MGNREGA Dashboard, Ministry of Rural Development, as accessed on August 12, 2024, https://mnregaweb4.nic.in/netnrega/state_html/unempall_new.aspx?fin_year=2023-2024&source=national&Digest=akdjO9VfTrWA9tZ+TJ0C7A.
[42] R 19.1 Unemployment Allowance in Financial Year 2024-25, NREGA Reports, Ministry of Rural Development, as accessed on January 22, 2025, https://mnregaweb4.nic.in/netnrega/state_html/unempall_new.aspx?fin_year=2024-2025&source=national&Digest=A5biDOmxWUswueiINVvFwg.
[43] Unstarred Question No 2480, Ministry of Rural Development, Lok Sabha, August 6, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/182/AU2480_6eVid3.pdf?source=pqals.
[44] Twenty Fifth Report of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj, Lok Sabha, August 3, 2022, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Rural%20Development%20and%20Panchayati%20Raj/17_Rural_Development_and_Panchayati_Raj_25.pdf?source=loksabhadocs.
[45] Overview of Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin (PMAY-G), Ministry of Rural Development, https://rural.gov.in/sites/default/files/Overview%20of%20PMAY-G.pdf.
[46] Houses for all under Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin, Press Information Bureau, Ministry of Rural Development, December 13, 2022, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1883183.
[47] Cabinet approves implementation of the Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin (PMAY-G) during FY 2024-25 to 2028-29, Ministry of Rural Development, PIB, August 9, 2024, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2043921.
[48] PMAY (G) Dashboard, Ministry of Rural Development, as accessed on January 22, 2025, https://pmayg.nic.in/netiay/PBIDashboard/PMAYGDashboard.aspx
[49] Thirty Three Report of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj (2022-23), July, 2023, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Rural%20Development%20and%20Panchayati%20Raj/17_Rural_Development_and_Panchayati_Raj_33.pdf?source=loksabhadocs.
[50] Audit Report on Local Bodies for the Year Ended 31 March, 2021, Comptroller and Auditor General of India, https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2023/Report-No.7-English-Local-Bodies-31.7.2023-signed---Copy-065c6066815de09.51627719.pdf.
[51] Performance Audit of Schemes of PRI, Audit Report (Local Bodies) for the year ended March 2021, Comptroller and Auditor General, https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2023/5.-Ch-2-Performance-Audit-of-schemes-0651c20629b58c1.50324227.pdf.
[52] Performance Audit on implementation of Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin, Government of Tamil Nadu, 2022, Comptroller and Auditor General of India, https://cag.gov.in/webroot/uploads/download_audit_report/2021/Report-No-6-of-2022-PMAY-G-2020-21-English-064427d5a33aa49.69300243.pdf.
[53] Impact Assessment of PMAY-G (Madhya Pradesh, Odisha & West Bengal), July, 2018, https://pmayg.nic.in/netiayHome/Document/PMAY-G-Research-Report-(NIRD&PR).pdf.
[54] Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Programme Guidelines, Ministry of Rural Development, January, 2015, https://pmgsy.nic.in/sites/default/files/pdf/PMGSY_E_J_2015.pdf.
[55] Programme Guidelines, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - II, https://pmgsy.nic.in/sites/default/files/pdf/PMGSY_Guidelines_Final.pdf.
[56] Programme Guidelines, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana – III, https://pmgsy.nic.in/sites/default/files/PMGSY_III_guidelines.pdf
[57] PMGSY Programme Guidelines for Road Connectivity Project for Left Wing Extremism Affected Area, Ministry of Rural Development, January, 2017, https://pmgsy.nic.in/sites/default/files/RCPLWEA22feb17.pdf.
[58] Beneficiaries under PM-JANMAN, Unstarred question no 623, Ministry of Tribal Affairs, Rajya Sabha, February 7, 2024, https://sansad.in/getFile/annex/263/AU623.pdf?source=pqars.
[59] PMGSY Dashboard, Ministry of Rural Development, as of January 22, 2025, https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTA2NzM0ZjAtNjhmMS00ZWE1LWIzMTUtY2Y3MjRjZTk5ZWQyIiwidCI6IjliZjc5NjA5LWU0ZTgtNDdhZC1hYTUzLTI0NjQ2MTg1NTM4YyJ9&pageName=ReportSection6c3e4a4e09e5c16ec50c.
[60] Cabinet approves implementation of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - IV (PMGSY-IV) during FY 2024-25 to 2028-29, Press Information Bureau, September 11, 2024, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2053894.
[61] Thirty Sixth Report on Action Taken on the Report on Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj (2023-24), Ministry of Rural Development, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Rural%20Development%20and%20Panchayati%20Raj/17_Rural_Development_and_Panchayati_Raj_36.pdf?source=loksabhadocs.
[62] Maintenance of Roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Ministry of Rural Development, Press Information Bureau, February 6, 2024, https://rural.gov.in/en/press-release/maintenance-roads-under-pradhan-mantri-gram-sadak-yojana.
[63] Quality Control, monitoring and evaluation, Performance Audit of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Comptroller and Auditor General of India, 2016, https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2016/Chapter_6_Quality_Control,_Monitoring_and_Evaluation.pdf.
[64] Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, NQM, Regarded Grading Abstract, as accessed on January 20, 2025, https://omms.nic.in/#
[65] Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, SQM, Regarded Grading Abstract, as accessed on January 20, 2025, https://omms.nic.in/#.
[66] eMARG, Ministry of Rural Development, as accessed on January 20, 2025, https://emarg.gov.in/application_main.htm.
[67] eMARG, electronic maintenance of rural roads, National Rural Infrastructure Development Agency (NRIDA), Ministry of Rural Development, as accessed on January 20, 2024, https://emarg.gov.in/pdf/publications/eMarg%20BOOKLET.pdf.
[68] Story of India being a developing country is a thing of the past, we are now vying with the best, Ministry of Power, Press Information Bureau, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1945906.
[69] Report of the Fifteenth Finance Commission, Volume III, https://fincomindia.nic.in/asset/doc/commission-reports/XVFC-Vol-III-Union.pdf.
[70] Programme Guidelines (PMGSY-III), Ministry of Rural Development, October, 2019, https://www.pmgsy.nic.in/sites/default/files/PMGSY_III_guidelines.pdf.
[71] Introduction, Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihood Mission, Ministry of Rural Development, accessed on June 15, 2024, https://aajeevika.gov.in/about/introduction.
[72] Bank Credit to Women SHGs, Unstarred Question No 3025, Ministry of Rural Development, Rajya Sabha, December 20, 2024, https://sansad.in/getFile/annex/266/AU3025_UtFvZ3.pdf?source=pqars.
[73] Dashboard, National Rural Livelihoods Mission, Ministry of Rural Development, as accessed on January 22, 2025, https://nrlm.gov.in/dashboardForOuter.do?methodName=dashboard.
[74] First report of the standing committee on rural development, Demand for Grants for 2024-25, Lok Sabha, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Rural%20Development%20and%20Panchayati%20Raj/18_Rural_Development_and_Panchayati_Raj_1.pdf?source=loksabhadocs.
[75] Status of Microfinance In India 2023-24, National Bank for Agriculture and Rural Development, https://www.nabard.org/auth/writereaddata/tender/0808244223NABARD-SOMFI%20%20%20%20%20%20%20%2020232024%20%20%20%20%20%2030072024.pdf.

[76] The loan repayment rate by SHGs to Banks is 97.71 percent, Ministry of Rural Development, Press Information Bureau, December 22, 2022, https://rural.gov.in/en/press-release/loan-repayment-rate-shgs-banks-9771-percent#:~:text=1%2C68%2C920.11%20Crores.-,The%20Loan%20repayment%20rate%20by%20SHGs%20to%20Banks%20is%2097.71,Mission%20(DAY%2DNRLM).
[77] National Rural Livelihoods Mission, Mission Guidelines, Ministry of Rural Development, https://rural.gov.in/sites/default/files/NRLM_Guidelines_English.pdf.
[78] Outcome of SHG bank linkage project, Unstarred Question no 1,219, Ministry of Rural Development, Rajya Sabha, December 13, 2023, https://sansad.in/getFile/annex/262/AU1219.pdf?source=pqars.
[79] Programme Guidelines, Deendayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana, Ministry of Rural Development, July 2016, https://rural.gov.in/sites/default/files/DDUGKY_Guidelines_English_1.pdf.
[80] State of Skills, International Labour Organisation, January 2020, https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/genericdocument/wcms_742201.pdf.
[81] Beneficiaries under Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana - DDU-GKY, Press Information Bureau, Ministry of Rural Development, December 17, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2085248#:~:text=Based%20on%20the%20implementation%20experiences,unit%20for%20training%20and%20placement.
[82] About Us, National Social Assistance Programme, Ministry of Rural Development, accessed on July 16, 2024, https://nsap.nic.in/circular.do?method=aboutus.
[83] Boosting Rural Economy Post-Coronavirus Pandemic, Ministry of Rural Development, Lok Sabha, February 2, 2021, https://sansad.in/getFile/annex/253/AU1420.pdf?source=pqars.
[84] Unstarred Question No 651, Increasing Pension Under NSAP, Ministry of Rural Development, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/1715/AU651.pdf?source=pqals
[85] Thirty Third Report on Demand for Grants, Ministry of Rural Development (Department of Rural Development), Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Rural%20Development%20and%20Panchayati%20Raj/17_Rural_Development_and_Panchayati_Raj_33.pdf?source=loksabhadocs
[86] Report of the Fifteenth Finance Commission, Volume – III, https://fincomindia.nic.in/asset/doc/commission-reports/XVFC-Vol-III-Union.pdf
[87] Report of the Comptroller and Auditor General of India on Performance Audit of National Social Assistance Programme, CAG, 2023, https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2023/Report-No.-10-of-2023_NSAP_English_PDF-A-064d229f832dad7.55068084.pdf.
[88] "About the Department", Department of Land Resources, accessed on July 17, 2024, https://dolr.gov.in/en/about-us/about-department.
[89] DILRMP, Department of Land Resources, as accessed on July 18, 2024, https://dolr.gov.in/programmes-schemes/dilrmp-2/.
[90] Watershed Development Component of PMKSY, Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, as accessed on July 17, 2024, https://dolr.gov.in/wdcpmksy/
[91] Twenty Third Report on Demand for Grants (2022-23), Standing Committee on Rural Development, March 16, 2022, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Rural%20Development%20and%20Panchayati%20Raj/17_Rural_Development_and_Panchayati_Raj_23.pdf?source=loksabhadocs
[92] Thirtieth Report on Demand for Grants (2023-24), Department of Land Resources, Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj, March 15, 2023, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Rural%20Development%20and%20Panchayati%20Raj/17_Rural_Development_and_Panchayati_Raj_30.pdf?source=loksabhadocs.
[93] Thirtieth Report on Demand for Grants (2023-24), Department of Land Resources, Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj, March 15, 2023, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Rural%20Development%20and%20Panchayati%20Raj/17_Rural_Development_and_Panchayati_Raj_30.pdf?source=loksabhadocs.
[94] Second Report of the Standing Committee on Rural Development, 18th Lok Sabha, December 12, 2024, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Rural%20Development%20and%20Panchayati%20Raj/18_Rural_Development_and_Panchayati_Raj_2.pdf?source=loksabhadocs
[95] Twenty Third Report on Demand for Grants (2022-23), Standing Committee on Rural Development, March 16, 2022, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Rural%20Development%20and%20Panchayati%20Raj/17_Rural_Development_and_Panchayati_Raj_23.pdf?source=loksabhadocs.
[96] Twenty Seventh Report on Demand for Grants (2022-23) of Department of Land Resources, Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj, August 3, 2022, https://loksabhadocs.nic.in/lsscommittee/Rural%20Development%20and%20Panchayati%20Raj/17_Rural_Development_and_Panchayati_Raj_27.pdf.
[97] Thirtieth Report on Demand for Grants (2023-24), Department of Land Resources, Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj, March 15, 2023, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Rural%20Development%20and%20Panchayati%20Raj/17_Rural_Development_and_Panchayati_Raj_30.pdf?source=loksabhadocs.
[98] Report T2 – State wise, district wise and project wise details of targets, achievements and works of activities till selected financial year, 2023=24, as accessed on July 18, 2024, https://wdcpmksy.dolr.gov.in/activityWiseUptoPlanAchievWork
[99] Operational Guidelines of Digital India Land Records Modernisation Programme (DILRMP), Ministry of Rural Development, 2019, https://dolr.gov.in/sites/default/files/Final%20%20Guideline%20of%20DILRMP%2002-01-2019.pdf.
[100] Annual Report 2022-23, Ministry of Land Resources, https://rural.gov.in/sites/default/files/AnnualReport2022_23_English_0.pdf.

स्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।